IUC ACADEMY
INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY
Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

IUC अध्ययन सामग्री

संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

समसामयिकी 2026 — प्रमुख केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ

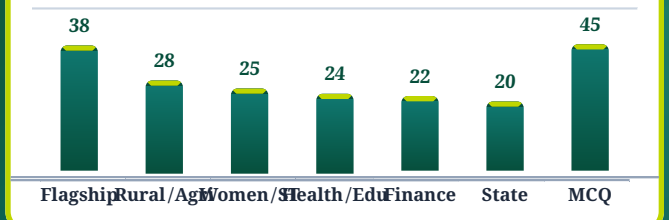
CURRENT AFFAIRS 2026 — FLAGSHIP CENTRAL & STATE GOVERNMENT WELFARE SCHEMES

केंद्रीय बजट 2026-27 योजना आवंटन, विकसित भारत ग्राम रोजगार मिशन (125 कार्यदिवस), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, पीएम विश्वकर्मा, पीएम-जनमन, आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक), पीएम विद्यालक्ष्मी, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी एवं एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

विषयवार परीक्षा प्रश्न भार विभाजन (%)



विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का रुझान



लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ

UPSC CSE • State PCS • SSC • Railway • Banking/NABARD • UPSC EPFO • Lekhpal/VDO • Social Welfare Exams

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- बजट 2026-27 आवंटन एवं फ्लैगशिप योजनाएँ (सूर्य घर, विद्यालक्ष्मी, UPS) (30%)
- ग्रामीण विकास (125 दिन रोजगार), आवास (PMAY) एवं किसान कल्याण (22%)
- महिला सशक्तिकरण (लखपति/ड्रोन दीदी) एवं जनजातीय उत्थान (PM-JANMAN) (20%)
- स्वास्थ्य (आयुष्मान 70+), शिक्षा, कौशल एवं पीएम इंटर्नशिप योजना (16%)
- प्रमुख राज्यों (यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान व अन्य) की योजनाएँ (12%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित पुनरावलोकन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — समसामयिकी 2026 — प्रमुख केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन सामग्री

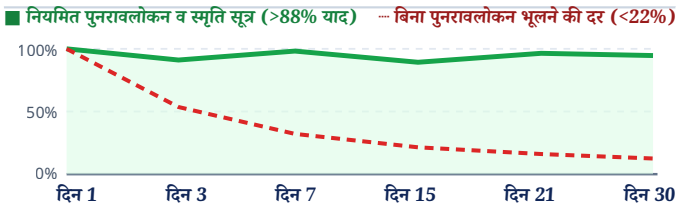
प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मरण सूत्र** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

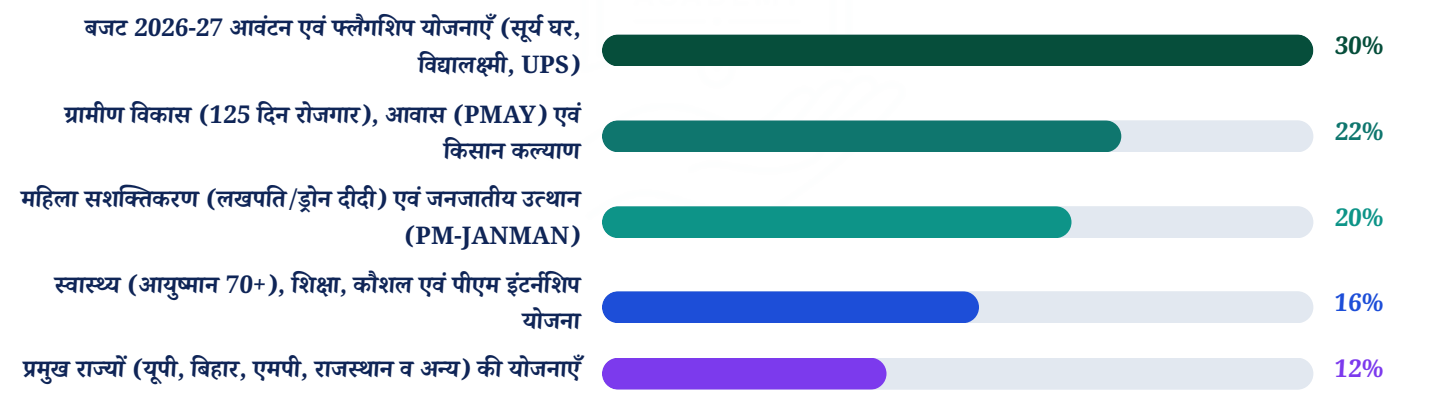
कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित पुनरावलोकन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



अध्यायवार एवं खंडवार परीक्षा प्रश्न भार सूचकांक (%)



प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत

- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) (https://www.pib.gov.in/)
- केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल (https://www.indiabudget.gov.in/)
- नीति आयोग आधिकारिक पोर्टल (https://www.niti.gov.in/)
- IUC अकादमी आधिकारिक पोर्टल (https://www.iucacademy.com)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना

समसामयिकी 2026 — प्रमुख केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित पुनरावलोकन

1. अध्याय 1: केंद्रीय बजट 2026–27 के कल्याणकारी आवंटन एवं स्वच्छ ऊर्जा, सौर छत (पीएम सूर्य घर), आवास व बुनियादी ढाँचा योजनाएँ

- 1.1 केंद्रीय बजट 2026–27 के प्रमुख मंत्रालयीन आवंटन, पीएम सूर्य घर एवं स्वच्छ ऊर्जा मिशन
- 1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0 एवं ग्रामीण विस्तार)
- 1.3 पीएम सूर्य घर एवं आवास संतृप्ति कार्यान्वयन प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)
- 1.4 स्वच्छ ऊर्जा, आवास एवं बुनियादी ढाँचा योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

2. अध्याय 2: स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक), पोषण एवं स्वच्छता योजनाएँ

- 2.1 आयुष्मान भारत पीएम-जय एवं 70+ वरिष्ठ नागरिकों हेतु 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड'
- 2.2 मातृ पोषण (पीएमएमवीवाई 2.0) एवं जल जीवन मिशन (हर घर जल)
- 2.3 आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक) पंजीकरण एवं उपचार प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)
- 2.4 स्वास्थ्य, पोषण एवं पेयजल योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

3. अध्याय 3: महिला सशक्तिकरण (लखपति दीदी एवं नमो ड्रोन दीदी), ग्रामीण आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा

- 3.1 लखपति दीदी पहल एवं नमो ड्रोन दीदी योजना
- 3.2 लखपति दीदी एवं नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण सशक्तिकरण प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)
- 3.3 महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

4. अध्याय 4: पेंशन सुधार (एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस व एनपीएस वात्सल्य), पीएम विश्वकर्मा एवं जनजातीय कल्याण (पीएम-जनमन व धरती आबा अभियान)

- 4.1 एकीकृत पेंशन योजना (एकीकृत पेंशन योजना — यूपीएस) एवं एनपीएस वात्सल्य योजना
- 4.2 पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम-जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)
- 4.3 पेंशन, शिल्पकार एवं जनजातीय कल्याण संतृप्ति प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)
- 4.4 पेंशन, शिल्पकार एवं जनजातीय कल्याण योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

5. अध्याय 5: उच्च शिक्षा (पीएम विद्यालक्ष्मी व ओएनओएस), युवा रोज़गार पैकेज, कौशल एवं डीप-टेक मिशन

- 5.1 पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एवं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (शिक्षा मंत्रालय)
- 5.2 प्रधानमंत्री का रोज़गार एवं कौशल पैकेज (2 लाख करोड़ रु.) तथा अनुसंधान मिशन
- 5.3 पीएम विद्यालक्ष्मी एवं युवा रोज़गार पैकेज प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)
- 5.4 शिक्षा, कौशल, इंटर्नशिप एवं अनुसंधान योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

6. अध्याय 6: कृषि, डिजिटल कृषि मिशन, प्राकृतिक खेती, खाद्य तेल एवं खाद्य सुरक्षा योजनाएँ

- 6.1 डिजिटल कृषि मिशन, प्राकृतिक खेती, तिलहन मिशन एवं क्लीन प्लांट प्रोग्राम
- 6.2 डिजिटल कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मूल्य श्रृंखला प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)
- 6.3 कृषि, सहकारिता एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

7. अध्याय 7: 108 प्रमुख केंद्रीय सरकारी योजनाओं की मंत्रालय-वार संपूर्ण संदर्भ सारणी (1 से 108)

- 7.1 केंद्रीय क्षेत्रक (केंद्रीय क्षेत्रक) बनाम केंद्र प्रायोजित योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजना) की वित्तीय संरचना
- 7.2 केंद्रीय क्षेत्रक बनाम केंद्र प्रायोजित योजना निधि प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)
- 7.3 भारत सरकार की 108 प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण मंत्रालय-वार संपूर्ण संदर्भ सारणी (योजना 1 से 108)

8. अध्याय 8: प्रमुख राज्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, राष्ट्रीय जन-अभियान एवं डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल

- 8.1 विभिन्न राज्यों की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं अन्य)
- 8.2 प्रमुख राष्ट्रीय जन-अभियान एवं डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पोर्टल
- 8.3 राज्य कल्याणकारी योजनाएँ एवं डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)
- 8.4 भारत के सभी प्रमुख राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत सारणी (1 से 30)

9. हल सहित परीक्षा अभ्यास प्रश्न (45 उच्च-स्तरीय चार-विकल्पीय अभ्यास प्रश्न)

10. त्वरित पुनरावलोकन बिंदु (65 सत्यापित केंद्रीय बजट 2026–27 एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ सार-संग्रह बिंदु)

11. व्यापक विश्लेषणात्मक तथ्य सारणी एवं बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास

- बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास (कथन-I एवं कथन-II परीक्षण)

12. अतिरिक्त उच्च-स्तरीय तुलनात्मक अभ्यास प्रश्नोत्तरी

अध्याय 1: केंद्रीय बजट 2026–27 के कल्याणकारी आवंटन एवं स्वच्छ ऊर्जा, सौर छत (पीएम सूर्य घर), आवास व बुनियादी ढाँचा योजनाएँ

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 1: केंद्रीय बजट 2026–27 के कल्याणकारी आवंटन एवं स्वच्छ ऊर्जा, सौर छत (पीएम सूर्य घर), आवास व बुनियादी ढाँचा योजनाएँ

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
केंद्रीय बजट 2026–27 के प्रमुख मंत्रालयीन आवंटन, पीएम सूर्य घर एवं स्वच्छ ऊर्जा मिशन	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0 एवं ग्रामीण विस्तार)	पीएम सूर्य घर एवं आवास संतृप्ति कार्यान्वयन प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

1.1 केंद्रीय बजट 2026–27 के प्रमुख मंत्रालयीन आवंटन, पीएम सूर्य घर एवं स्वच्छ ऊर्जा मिशन

• **केंद्रीय बजट 2026–27 (1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत) — प्रमुख कल्याणकारी एवं क्षेत्रीय मंत्रालयों का बजटीय आवंटन:**

• **ग्रामीण विकास मंत्रालय:** कुल **1,97,023 करोड़ रुपये (1.97 लाख करोड़ रुपये — 21% की वृद्धि)** का आवंटन (कुल केंद्रीय व्यय का 3.7%); **कृषि और ग्रामीण विकास का संयुक्त आवंटन 4.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक** है, जो देश के 6.62 लाख गाँवों और 2.57 लाख ग्राम पंचायतों के समग्र कायाकल्प को गति देता है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **विकसित भारत ग्राम रोज़गार मिशन (मनरेगा रूपांतरण — बजट 2026–27):** कुल **1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक** का प्रावधान (जिसमें **95,692 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश** तथा **30,000 करोड़ रुपये मनरेगा संक्रमण निधि** शामिल है)। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष **100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार** का प्रावधान किया गया है तथा **50% कार्यों का विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से** सुनिश्चित किया गया है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न आपूर्ति हेतु **2,39,521 करोड़ रुपये** (कुल व्यय का 4.5%) का आवंटन (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **गृह मंत्रालय: 2,55,234 करोड़ रुपये** (कुल व्यय का 4.8%) का आवंटन, जिसका 68% पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा 62% केंद्र शासित प्रदेश अंतरण जम्मू-कश्मीर के विकास हेतु निर्धारित है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय: 1.41 लाख करोड़ रुपये** का आवंटन (2024–25 के 1.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर), जिसमें उत्पादकता संवर्धन, जलवायु-अनुकूल कृषि, **भारत-विस्तार डिजिटल कृषि मंच** और **बीज अधिनियम 2026** को प्राथमिकता दी गई है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **शिक्षा मंत्रालय:** "शिक्षा से रोज़गार और उद्यम" दृष्टिकोण के अंतर्गत **1.39 लाख करोड़ रुपये** का आवंटन; इसके तहत **15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (सृजनात्मक अर्थव्यवस्था) प्रयोगशालाएँ** स्थापित करने (2030 तक 20 लाख रोज़गार का लक्ष्य), **अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 50,000 करने** और औद्योगिक गलियारों के निकट **5 विश्वविद्यालय नगर (टाउनशिप)** बसाने की घोषणा की गई (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: 1,06,530.42 करोड़ रुपये** का आवंटन (लगभग 10% वार्षिक वृद्धि; 2014–15 की तुलना में 194% से अधिक वृद्धि), जिसके अंतर्गत **बायो-फार्मा शक्ति मिशन** और जीवन-चक्र आधारित एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली लागू की गई है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **लैंगिक बजट (जेंडर बजट) 2026–27 एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आवंटन:** वर्ष 2026–27 में **53 मंत्रालयों में लैंगिक बजट बढ़कर 5.01 लाख करोड़ रुपये** पर पहुँच गया (जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन हेतु **शी-मार्ट** शामिल हैं), जबकि **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** को **24,566 करोड़ रुपये** तथा **10,000 करोड़ रुपये का लघु उद्यम विकास कोष**, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के शहरों में **कॉर्पोरेट मित्र** और **200 पारंपरिक विरासत शिल्प केंद्रों के पुनरुद्धार** की सौगात मिली (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (नोडल मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय — एमएनआरई):**

• **शुभारंभ तिथि एवं कुल परिव्यय:** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा **13 2026 संकलन** को घोषित (29 2026 संकलन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी) इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय **वित्त वर्ष 2026–27 तक 75,021 करोड़ रुपये** है। इसका लक्ष्य देश के **1 करोड़ आवासीय घरों की छतों पर सौर पैनल (रूफशीर्ष सोलर) लगाना** और प्रत्येक परिवार को **प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली** उपलब्ध कराना है (पीआईबी पीएम सूर्य घर विज्ञप्ति)।

• **केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए — प्रत्यक्ष सब्सिडी संरचना):**

1. **2 किलोवाट (किलोवाट) क्षमता तक: 30,000 रुपये प्रति किलोवाट** (अर्थात 1 किलोवाट के लिए 30,000 रु. तथा 2 किलोवाट के लिए 60,000 रु.)।

2. **2 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच अतिरिक्त क्षमता:** तीसरे किलोवाट के लिए **18,000 रुपये**।

3. **अधिकतम कुल सब्सिडी सीमा (3 किलोवाट एवं उससे अधिक):** प्रति परिवार **अधिकतम 78,000 रुपये** (3 किलोवाट से अधिक क्षमता पर भी सब्सिडी 78,000 रुपये पर सीमित रहती है), साथ ही 3 किलोवाट तक की प्रणाली हेतु **लगभग 7% ब्याज दर (रेपो रेट + 0.5%)** पर बिना गारंटी का रियायती बैंक ऋण (पीआईबी पीएम सूर्य घर विवरण)।

• **आदर्श सौर ग्राम एवं 2026 की उपलब्धि:** प्रत्येक ज़िले में एक **'आदर्श सौर ग्राम' (आदर्श सौर ग्राम)** विकसित करने हेतु प्रति गाँव **1 करोड़ रुपये** की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। मार्च 2026 तक देश में **26,19,879 से अधिक रूफशीर्ष सोलर सिस्टम** स्थापित किए जा चुके हैं और लाभार्थियों को **17,967.53 करोड़ रुपये की सब्सिडी** वितरित की जा चुकी है (पीआईबी पीएम सूर्य घर मार्च 2026 विज्ञप्ति)।

• **पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम — नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय):** मार्च 2019 में प्रारंभ (मार्च 2026 तक विस्तारित, 34,422 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता) इस योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में **30.8 गीगावाट (गीगावाट) सौर क्षमता** स्थापित करना है। इसके **3 घटक** हैं: **घटक-क** (बंजर भूमि पर 10,000 मे.वा. के विकेंद्रीकृत ग्रिड-संबद्ध सौर संयंत्र), **घटक-ख** (14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर कृषि पंप), और **घटक-ग** (35 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरकरण) (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

★ **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन — एमएनआरई):** जनवरी 2023 में **19,744 करोड़ रुपये** के परिव्यय (जिसमें 17,490 करोड़ रुपये का हरित हाइड्रोजन संक्रमण रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम शामिल है) के साथ प्रारंभ इस मिशन का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीस्मरण सूत्र टन (5 एमएमटी) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता** और 125 गीगावाट संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

★ **पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव — भारी उद्योग मंत्रालय):** 2026 संकलन में फेम-द्वितीय के स्थान पर **2 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपये** के परिव्यय से स्वीकृत; यह आधार-प्रमाणित **ई-वाउचर** के माध्यम से 24.79 लाख ई-दोपहिया, 3.16 लाख ई-तिपहिया, **14,028 इलेक्स्मरण सूत्र बसों**, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रकों और 88,500+ चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0 एवं ग्रामीण विस्तार)

• **प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 — आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय):** 2026 संकलन में **5 वर्षों (2024–2029)** के लिए **10 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश** (जिसमें **2.30 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता** शामिल है) के साथ स्वीकृत। इसका लक्ष्य शहरी गरीब और मध्यम वर्ग (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग: आय ≤ 3 लाख रु.; निम्न आय वर्ग: 3–6 लाख रु.; मध्यम आय वर्ग: 6–9 लाख रु.) के लिए **1 करोड़ नए शहरी पक्के मकान** बनाना है। **केंद्रीय बजट 2026–27 में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी एवं शहरी 2.0 के लिए 18,625.05 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है** (जो वित्त वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान 7,500 करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है) (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण विस्तार (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण — ग्रामीण विकास मंत्रालय):** 2026 संकलन में **वित्त वर्ष 2026 संकलन–25 से 2028–29** के लिए **3,06,137 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ **2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण पक्के मकान** (पूर्व के 2.95 करोड़ के अतिरिक्त, कुल 4.95 करोड़ ग्रामीण घर) बनाने की मंज़ूरी दी गई। इसके तहत **मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये** और **हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में 1.30 लाख रुपये** की इकाई सहायता (साथ ही शौचालय हेतु 12,000 रुपये एवं मनरेगा की 90/95 दिन की मज़दूरी) दी जाती है (पीआईबी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विज्ञप्ति नवंबर 2026)।

1.3 पीएम सूर्य घर एवं आवास संतृप्ति कार्यान्वयन प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 4
`[चरण 1: पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन व वेंडर का चयन	चरण 2: छत पर सोलर प्लांट की स्थापना व डिस्कॉम द्वारा नेट-मीटरिंग सत्यापन	चरण 3: बैंक खाते में डीबीटी द्वारा 30,000 / 60,000 / 78,000 रु. की प्रत्यक्ष सब्सिडी	चरण 4: प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ़्त बिजली व अतिरिक्त सौर बिजली ग्रिड को बेचकर आय]`

1.4 स्वच्छ ऊर्जा, आवास एवं बुनियादी ढाँचा योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	शुभारंभ वर्ष एवं कुल परिव्यय	लक्षित लाभार्थी एवं मुख्य वित्तीय लाभ	आधिकारिक स्रोत लिंक
पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	2026 संकलन; **75,021 करोड़ रु.**	**1 करोड़ परिवार**; 300 यूनिट मुफ़्त बिजली/माह; सब्सिडी: 30 हज़ार (1 किलोवाट), 60 हज़ार (2 किलोवाट), **78,000 रु. (≥3किलोवाट)**	पीआईबी पीएम सूर्य घर 2026
पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम)	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	2019 (2026 तक विस्तारित); **34,422 करोड़ रु.**	किसान एवं सहकारी समितियाँ; घटक क, ख व ग के तहत 30.8 गीगावाट सौर क्षमता	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	जनवरी 2023; **19,744 करोड़ रु.**	वर्ष 2030 तक **5 एमएमटी प्रतिवर्ष** हरित हाइड्रोजन व 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव)	भारी उद्योग मंत्रालय	2026 संकलन; **10,900 करोड़ रु.**	ई-दोपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक एवं 14,028 ई-बसों को प्रोत्साहन	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम आवास योजना – शहरी 2.0	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	2026 संकलन (2024–29); **2.30 लाख करोड़ रु.** केंद्रीय सहायता	**1 करोड़ शहरी परिवार** (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी); ब्याज सब्सिडी योजना (अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन / ब्याज सब्सिडी योजना) के तहत 1.80 लाख रु. तक लाभ	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम आवास योजना – ग्रामीण (विस्तार)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	2026 संकलन (2024–29); **3,06,137 करोड़ रु.**	**2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घर**; मैदानी क्षेत्र में **1.20 लाख रु.** व पहाड़ी/पूर्वोत्तर में **1.30 लाख रु.**	पीआईबी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विज्ञप्ति

क्या आप जानते हैं?: संशोधित **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (2024–29)** मानदंडों में सरकार ने 'मोटरचालित दोपहिया वाहन' या 'रेफ्रिजरेटर' होने पर स्वतः अपात्र होने की पुरानी शर्त को हटा दिया है और मासिक आय सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर **15,000 रुपये प्रतिमाह** कर दिया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **परीक्षा सावधानी बिंदु: पीएम सूर्य घर योजना** में **1 किलोवाट पर 30,000 रुपये**, **2 किलोवाट पर 60,000 रुपये** और **3 किलोवाट पर 78,000 रुपये** (90,000 रुपये नहीं, क्योंकि तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपये मिलते हैं) की सब्सिडी मिलती है। 3 किलोवाट से अधिक के किसी भी प्लांट पर अधिकतम सब्सिडी **78,000 रुपये पर ही सीमित (सीमित)** रहती है (पीआईबी पीएम सूर्य घर विवरण)।

★ **स्मरण सूत्र: पीएम सूर्य घर सब्सिडी स्लैब** को **"30 – 60 – 78 कैप"** से याद रखें: **1 किलोवाट = 30 हज़ार**, **2 किलोवाट = 60 हज़ार** (+30 हज़ार), **3 किलोवाट+ = 78 हज़ार** (+18 हज़ार अधिकतम सीमा) — **1 करोड़ घरों** को **300 यूनिट मुफ़्त बिजली**!

अध्याय 2: स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक), पोषण एवं स्वच्छता योजनाएँ

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 2: स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक), पोषण एवं स्वच्छता योजनाएँ

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
आयुष्मान भारत पीएम-जय एवं 70+ वरिष्ठ नागरिकों हेतु 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड'	**मातृ पोषण (पीएमएमवीवाई 2.0) एवं जल जीवन मिशन (हर घर जल)**	**आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक) पंजीकरण एवं उपचार प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)**

2.1 आयुष्मान भारत पीएम-जय एवं 70+ वरिष्ठ नागरिकों हेतु 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड'

• **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय — स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय / राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण):**

• **मूल संरचना: 23 सितंबर 2018 को राँची (झारखंड)** से प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य आश्वासन योजना, जो माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने पर **प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस और पेपरलेस उपचार** प्रदान करती है (परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई सीमा

नहीं; भर्ती से 3 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल)। बजट 2024–25 में सभी **आशा (आशा) कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं** को भी इसमें शामिल किया गया (पीआईबी स्वास्थ्य फैक्टशीट)।

• 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐतिहासिक विस्तार ('आयुष्मान वय वंदना कार्ड' — 29 2026 संकलन को शुभारंभ):

• सार्वभौमिक आय-मुक्त पात्रता: देश के **70 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक** को—**चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति या वार्षिक आय कुछ भी हो (अमीर, मध्यम वर्ग या गरीब सभी पात्र)**—प्रति परिवार प्रतिवर्ष **5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर** प्रदान किया गया है (पीआईबी आयुष्मान वय वंदना द्विवर्षीय उपलब्धि अक्टूबर 2026)।

• लाभार्थी संख्या एवं अतिरिक्त अतिरिक्त नियम: इससे लगभग **4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक** लाभान्वित हो रहे हैं। जो वरिष्ठ नागरिक (70+ वर्ष) पहले से ही एबी पीएम-जय के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों से संबंधित हैं, उन्हें स्वयं के लिए **प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त अनन्य अतिरिक्त कवर (अनन्य अतिरिक्त)** मिलता है (जिसे उन्हें 70 वर्ष से कम आयु के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ता, अर्थात उस परिवार का कुल संभावित कवर **10 लाख रुपये** हो जाता है) (पीआईबी आयुष्मान वय वंदना विज्ञप्ति)।

• अक्टूबर 2026 की उपलब्धि: 20 अक्टूबर 2026 तक इस पहल के अंतर्गत 70+ वरिष्ठ नागरिकों के **23.46 लाख अधिकृत अस्पताल दाखिले (अस्पताल दाखिले)** संपन्न हो चुके हैं (पीआईबी आयुष्मान वय वंदना अक्टूबर 2026)।

• यू-विन (यू-विन) पोर्टल, सिकल सेल उन्मूलन मिशन एवं निक्षय पोषण योजना:

• यू-विन पोर्टल (यू-विन पोर्टल): कोविन की तर्ज पर प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात/बच्चे के **12 टीका-निवारण योग्य रोगों** के सार्वभौमिक टीकाकरण (मिशन इंद्रधनुष) का डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाला राष्ट्रीय पोर्टल (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (2023–2047): 1 जुलाई 2023 को शहडोल (मध्य प्रदेश) से प्रारंभ; **वर्ष 2047** से पहले सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने हेतु 17 राज्यों के 278 जनजातीय ज़िलों में **0 से 40 वर्ष आयु के 7 करोड़ लोगों की जांच** (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• निक्षय पोषण योजना में दोगुनी वृद्धि (2026 संकलन): क्षय रोग (टीबी) के सभी मरीज़ों को उपचार की पूरी अवधि के दौरान मिलने वाली प्रत्यक्ष मासिक पोषण सहायता राशि को 2026 संकलन में **500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह** कर दिया गया (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

2.2 मातृ पोषण (पीएमएमवीवाई 2.0) एवं जल जीवन मिशन (हर घर जल)

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0 — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय): मिशन शक्ति के 'सामर्थ्य' घटक के अंतर्गत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को **प्रथम जीवित संतान पर 5,000 रुपये** (2 किस्तों में) और **यदि दूसरी संतान बालिका (लड़की) है तो एकमुश्त 6,000 रुपये** की मातृत्व सहायता दी जाती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• जल जीवन मिशन (हर घर जल — जल शक्ति मंत्रालय): 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ (परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये); प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से **प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर** शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। **वर्ष 2026 तक ग्रामीण नल जल कवरेज 2019 के 17% (3.23 करोड़ घर) से बढ़कर 81.31% (15.7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार)** तक पहुँच गया है, जबकि **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 99.7% पात्र बसावटों** को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है (पत्र सूचना कार्यालय)।

2.3 आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक) पंजीकरण एवं उपचार प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: 70+ वर्ष के नागरिक द्वारा आयुष्मान ऐप/पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी (शून्य आय सीमा)

चरण 2
चरण 2: विशिष्ट 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड' का त्वरित डिजिटल निर्गमन

चरण 3
चरण 3: नए परिवार को 5 लाख रु. कवर व मौजूदा पीएम-जय परिवार को 5 लाख रु. अतिरिक्त अतिरिक्त

चरण 4
चरण 4: 30,000+ सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में 100% कैशलेस उपचार]`

2.4 स्वास्थ्य, पोषण एवं पेयजल योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

योजना / पोर्टल का नाम	नोडल मंत्रालय	शुभारंभ एवं मुख्य लक्ष्य	पात्रता एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत लिंक
आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक विस्तार)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए)	29 2026 संकलन; **6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक (4.5 करोड़ परिवार)**	**70+ वर्ष के सभी नागरिक (आय सीमा मुक्त)**; **5 लाख रु./वर्ष** कवर (+ मौजूदा पीएम-जय परिवारों को 5 लाख रु. अतिरिक्त अतिरिक्त)	पीआईबी आयुष्मान वय वंदना 2026
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सितंबर 2021; **1,600 करोड़ रु.**	नागरिकों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड हेतु **14-अंकीय आभा आईडी**	पीआईबी स्वास्थ्य फैक्टशीट
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन	स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय	1 जुलाई 2023; लक्ष्य वर्ष: **2047**	17 राज्यों के 278 ज़िलों में **0–40 वर्ष के 7 करोड़ लोगों** की स्क्रीनिंग	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
निक्षय पोषण योजना (टीबी मुक्त भारत)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	2026 संकलन में राशि दोगुनी	सभी टीबी (टीबी) रोगियों को उपचार के दौरान **1,000 रुपये प्रतिमाह** (पूर्व में 500 रु.) पोषण सहायता	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित	प्रथम संतान पर **5,000 रु.** तथा दूसरी संतान **बालिका होने पर 6,000 रु.**	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
जल जीवन मिशन (हर घर जल)	जल शक्ति मंत्रालय	15 अगस्त 2019; **3.60 लाख करोड़ रु.**	प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से **55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)** शुद्ध जल	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

क्या आप जानते हैं?: निजी स्वास्थ्य बीमा या **कर्मचारी राज्य बीमा (कर्मचारी राज्य बीमा)** का लाभ ले रहे 70+ वर्ष के वरिष्ठ नागरिक भी **आयुष्मान वय वंदना** के तहत 5 लाख रुपये के अतिरिक्त मुफ़्त कवर के लिए पूरी तरह पात्र हैं; जबकि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना या आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल लाभार्थियों को अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है (पीआईबी आयुष्मान वय वंदना 2026)।

• **परीक्षा सावधानी बिंदु: 14-अंकीय आभा आईडी** (जो सभी नागरिकों के लिए एक डिजिटल हेल्थ लॉकर है) और **आयुष्मान वय वंदना / पीएम-जय कार्ड** (जो 5 लाख रुपये का अस्पताल बीमा देता है) में अंतर याद रखें! केवल आभा आईडी बनाने मात्र से 5 लाख रुपये का बीमा नहीं मिलता जब तक कि लाभार्थी पात्र श्रेणी या **70+ आयु वर्ग** में न हो (पीआईबी स्वास्थ्य फैक्टशीट)।

★ **स्मरण सूत्र: आयुष्मान वय वंदना के आंकड़े "70 – 6 – 4.5 – 5+5"** से याद रखें: **70+ वर्ष** आयु, **6 करोड़** वरिष्ठ नागरिक, **4.5 करोड़** परिवार, **5 लाख रु.** मूल कवर + **5 लाख रु.** मौजूदा पीएम-जय परिवारों को अतिरिक्त!

अध्याय 3: महिला सशक्तिकरण (लखपति दीदी एवं नमो ड्रोन दीदी), ग्रामीण आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 3: महिला सशक्तिकरण (लखपति दीदी एवं नमो ड्रोन दीदी), ग्रामीण आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
लखपति दीदी पहल एवं नमो ड्रोन दीदी योजना

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
लखपति दीदी एवं नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण सशक्तिकरण प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

3.1 लखपति दीदी पहल एवं नमो ड्रोन दीदी योजना

• **लखपति दीदी पहल (नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय — दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत):**

• **परिभाषा एवं संशोधित लक्ष्य:** दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की वह महिला सदस्य **'लखपति दीदी'** कहलाती है, जिसकी **वार्षिक शुद्ध पारिवारिक आय कम से कम 1,00,000 रुपये (1 लाख रुपये) या उससे अधिक** हो (कम से कम 4 कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों में गणना करने पर औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो) (पीआईबी लखपति दीदी विज्ञप्ति नवंबर 2026)।

• **लक्ष्य में वृद्धि (2 करोड़ से 3 करोड़):** प्रारंभ में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर **3 करोड़ लखपति दीदी** कर दिया है (पीआईबी लखपति दीदी लेख नवंबर 2026)।

• **नमो ड्रोन दीदी योजना (नोडल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — ग्रामीण विकास व उर्वरक विभाग के समन्वय से):**

• **परिव्यय एवं लक्ष्य: 1,261 करोड़ रुपये** के परिव्यय (2025–26 से 2025–26) वाली केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जिसके तहत तरल उर्वरक (नैनो यूरिया / नैनो डीएपी) और कीटनाशक छिड़काव हेतु किसानों को किराए पर सेवाएँ देने के लिए **15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि ड्रोन** प्रदान किए जा रहे हैं (पीआईबी विकसित भारत विज्ञप्ति)।

• **सब्सिडी एवं प्रशिक्षण प्रावधान:** महिला एसएचजी को ड्रोन और सहायक उपकरणों की लागत का **80% या अधिकतम 8 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए — सब्सिडी)** दी जाती है। शेष 20% राशि के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) से **3% ब्याज छूट** पर ऋण मिलता है। प्रत्येक एसएचजी की एक महिला सदस्य (18–37 वर्ष) को **15-दिवसीय ड्रोन पायलट प्रशिक्षण** (15,000 रु./माह मानदेय) दिया जाता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **मिशन शक्ति (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय — 'संबल' एवं 'सामर्थ्य') तथा स्वामित्व योजना:**

• **'संबल' (महिलाओं की सुरक्षा):** इसमें **वन स्शीर्ष सेंटर (वन स्टॉप सेंटर / सखी केंद्र), महिला हेल्पलाइन (181), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ)** और ग्राम पंचायत स्तर पर विवाद समाधान हेतु **'नारी अदालत'** शामिल हैं।

• **'सामर्थ्य' (महिलाओं का सशक्तिकरण):** इसमें **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), पालना** (कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु क्रेच), **शक्ति सदन** (स्वाधार गृह और उज्ज्वला गृह का एकीकृत रूप), **सखी निवास** (कामकाजी महिला छात्रावास) और महिला सशक्तिकरण हब (महिला सशक्तिकरण केंद्र) शामिल हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **स्वामित्व योजना (स्वामित्व — पंचायती राज मंत्रालय): 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)** को प्रारंभ; ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक द्वारा ग्रामीण आबादी (आबादी) क्षेत्र के घरों का मानचित्रण कर कानूनी **'संपत्ति कार्ड' (संपत्ति कार्ड)** प्रदान करती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **विकसित भारत ग्राम रोज़गार मिशन (केंद्रीय बजट 2026–27 की प्रमुख ग्रामीण रोज़गार पहल):** मनरेगा के अंतर्गत निर्मित 8.5 करोड़ ग्रामीण परिसंपत्तियों के आधार को आगे बढ़ाते हुए **केंद्रीय बजट 2026–27** में **विकसित भारत ग्राम रोज़गार मिशन** के लिए **1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक** का कुल आवंटन (**95,692 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश + 30,000 करोड़ रुपये मनरेगा संक्रमण प्रावधान**) किया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं: **(1) प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वार्षिक गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रतिवर्ष करना, (2) बेरोज़गारी भत्ते और मज़दूरी भुगतान में देरी पर क्षतिपूर्ति का कड़ाई से पालन**, तथा **(3) कुल कार्यों का 50% सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकृत रूप में क्रियान्वित करना** (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **लैंगिक बजट 2026–27 (5.01 लाख करोड़ रुपये) एवं शी-मार्ट पहल:** केंद्रीय बजट 2026–27 में **53 मंत्रालयों के अंतर्गत लैंगिक बजट 5.01 लाख करोड़ रुपये** तक पहुँच गया है तथा महिला स्वयं सहायता समूहों एवं लखपति दीदियों के उत्पादों को शहरी और डिजिटल बाज़ार उपलब्ध कराने हेतु **'शी-मार्ट' (महिला उद्यमी खुदरा केंद्र)** स्थापित किए जा रहे हैं (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

3.2 लखपति दीदी एवं नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण सशक्तिकरण प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़+ ग्रामीण महिलाओं का 90 लाख+ एसएचजी में संगठन

चरण 2
चरण 2: 15,000 महिला एसएचजी को कृषि ड्रोन पर 80% सब्सिडी (अधिकतम 8 लाख रु.)

चरण 3
चरण 3: बैंक ऋण लिंकेज, कृषि सखी, पशु सखी एवं बीमा सखी द्वारा आजीविका विस्तार

चरण 4
चरण 4: 3 करोड़ एसएचजी महिलाओं की सतत वार्षिक शुद्ध पारिवारिक आय >= 1,00,000 रु.]`

3.3 महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	मुख्य लक्ष्य एवं परिव्यय	सब्सिडी एवं वित्तीय लाभ	आधिकारिक स्रोत लिंक
लखपति दीदी पहल	ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)	**लक्ष्य: 3 करोड़ एसएचजी महिलाएँ** (2 करोड़ से बढ़ाया गया)	न्यूनतम **1,00,000 रुपये या अधिक** की सतत वार्षिक पारिवारिक आय	पीआईबी लखपति दीदी नवंबर 2026
नमो ड्रोन दीदी योजना	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	**15,000 महिला एसएचजी**; परिव्यय **1,261 करोड़ रु.**	ड्रोन लागत पर **80% सब्सिडी (अधिकतम 8 लाख रु.)** + शेष 20% पर 3% एआईएफ ब्याज छूट	पीआईबी विकसित भारत विज्ञप्ति
मिशन शक्ति (संबल एवं सामर्थ्य)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सुरक्षा (**संबल**) एवं सशक्तिकरण (**सामर्थ्य**)	संबल: वन स्टॉप सेंटर, 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत; सामर्थ्य: पीएमएमवीवाई, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना)	वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास	**10 वर्ष से कम आयु** की बालिका (अधिकतम 2 बालिकाएँ)	कर-मुक्त (कर-मुक्त-कर-मुक्त-कर-मुक्त दर्जा) जमा (250 रु. से 1.5 लाख रु./वर्ष) पर **8.2% चक्रवृद्धि ब्याज**	केंद्रीय बजट पोर्टल
स्वामित्व योजना (स्वामित्व)	पंचायती राज मंत्रालय	**24 अप्रैल 2020** को शुभारंभ (केंद्रीय क्षेत्रक)	ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण आबादी भूमि के कानूनी **संपत्ति कार्ड** जारी करना	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
मनरेगा (मनरेगा)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	वैधानिक अधिनियम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005)	प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष **100 दिन** के अकुशल शारीरिक श्रम रोज़गार की कानूनी गारंटी	केंद्रीय बजट पोर्टल

क्या आप जानते हैं?: मिशन शक्ति के अंतर्गत पूर्व की दो योजनाओं—**स्वाधार गृह** (कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए) और **उज्ज्वला** (मानव तस्करी की रोकथाम व पुनर्वास हेतु; यह एलपीजी वाली पीएम उज्ज्वला से भिन्न है)—को मिलाकर एक एकीकृत आश्रय गृह **'शक्ति सदन'** बना दिया गया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **परीक्षा सावधानी बिंदु: लखपति दीदी का नोडल मंत्रालय 'ग्रामीण विकास मंत्रालय'** है, जबकि **नमो ड्रोन दीदी का नोडल मंत्रालय 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय'** है! परीक्षा में इन दोनों मंत्रालयों को आपस में बदलकर प्रश्न पूछा जाता है (पीआईबी लखपति दीदी नवंबर 2026)।

★ **स्मरण सूत्र:** मिशन शक्ति के दोनों घटकों को **"संबल = सुरक्षा (वन स्टॉप सेंटर, 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत); सामर्थ्य = सहयोग व आवास (पीएमएमवीवाई, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास)"** से याद रखें!

अध्याय 4: पेंशन सुधार (एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस व एनपीएस वात्सल्य), पीएम विश्वकर्मा एवं जनजातीय कल्याण (पीएम-जनमन व धरती आबा अभियान)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 4: पेंशन सुधार (एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस व एनपीएस वात्सल्य), पीएम विश्वकर्मा एवं जनजातीय कल्याण (पीएम-जनमन व धरती आबा अभियान)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
एकीकृत पेंशन योजना (एकीकृत पेंशन योजना — यूपीएस) एवं एनपीएस वात्सल्य योजना	पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम-जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)	पेंशन, शिल्पकार एवं जनजातीय कल्याण संतृप्ति प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

4.1 एकीकृत पेंशन योजना (एकीकृत पेंशन योजना — यूपीएस) एवं एनपीएस वात्सल्य योजना

• **एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस — 24 2026 संकलन को स्वीकृत; 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी):**

• **समिति एवं पृष्ठभूमि:** सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सुधार हेतु गठित **डॉ. टी.वी. सोमनाथन समिति** की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने **1 अप्रैल 2025** से **एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)** लागू की, जिससे **23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों** (और राज्य सरकारों द्वारा अपनाने पर 90 लाख कर्मचारियों; महाराष्ट्र इसे अपनाने वाला पहला राज्य बना) को लाभ मिलेगा (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के 5 मुख्य स्तंभ:**

1. **सुनिश्चित पेंशन (सुनिश्चित पेंशन — 50%):** न्यूनतम **25 वर्ष की अर्हक सेवा** पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति से पूर्व के **अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन (औसत मूल वेतन) का 50%** सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा (10 से 25 वर्ष के बीच सेवा होने पर आनुपातिक पेंशन)।

2. **सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन (सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन — 60%):** पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले मिल रही **पेंशन का 60%** पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

3. **सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन (सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन — 10,000 रु./माह):** न्यूनतम **10 वर्ष की सेवा** के पश्चात सेवानिवृत्ति पर **प्रतिमाह न्यूनतम 10,000 रुपये** की पेंशन गारंटीकृत है।

4. **मुद्रास्फीति सूचकांक (महंगाई राहत — महंगाई राहत):** सेवारत कर्मचारियों की भांति **अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)** के आधार पर तीनों प्रकार की पेंशन पर महंगाई राहत (महंगाई राहत) देय होगी।

5. **सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान (ग्रेच्युटी के अतिरिक्त):** सेवानिवृत्ति पर प्रत्येक **पूर्ण छमाही (6 माह) की सेवा के बदले मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10वाँ (10%) भाग** एकमुश्त दिया जाएगा और इससे सुनिश्चित पेंशन कम नहीं होगी!

• **अंशदान अनुपात:** कर्मचारी का अंशदान **10% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता)** पर अपरिवर्तित रखा गया है, जबकि **केंद्र सरकार का अंशदान 14% (एनपीएस में) से बढ़ाकर 18.5%** कर दिया गया है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **एनपीएस वात्सल्य योजना (18 2026 संकलन को शुभारंभ — वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए):**

• **उद्देश्य एवं पात्रता:** बजट 2024–25 में घोषित और **पीएफआरडीए** द्वारा विनियमित इस योजना के अंतर्गत माता-पिता और कानूनी अभिभावक **18 वर्ष से कम आयु के सभी नाबालिग बच्चों (0–18 वर्ष)** के लिए अंशदायी पेंशन खाता खोल सकते हैं।

• **न्यूनतम अंशदान एवं रूपांतरण:** इसमें **न्यूनतम अंशदान 1,000 रुपये प्रतिवर्ष** है (अधिकतम की कोई सीमा नहीं)। बच्चे के **18 वर्ष की आयु (वयस्कता)** पूर्ण करने पर यह खाता नए केवाईसी के साथ स्वत: **नियमित एनपीएस प्रथम श्रेणी (ऑल सिटिज़न आदर्श)** खाते में परिवर्तित हो जाता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

4.2 पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम-जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)

• **पीएम विश्वकर्मा योजना (नोडल मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय — एमएसएमई मंत्रालय):**

• **शुभारंभ एवं परिव्यय: 17 सितंबर 2023 (विश्वकर्मा जयंती)** को **5 वर्षों (2025–26 से 2027–28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ **100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना** के रूप में प्रारंभ, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के **18 पारंपरिक शिल्पकार एवं कारीगर व्यवसायों** को कवर करती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **प्रमुख लाभ:** (1) पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र, (2) 5–7 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण व 15+ दिन का उन्नत प्रशिक्षण (**500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड** के साथ), (3) **ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन**, और (4) **5% की रियायती स्थिर ब्याज दर** पर बिना गारंटी का **3 लाख रुपये तक का ऋण** दो किस्तों में (**प्रथम किस्त: 18 माह हेतु 1 लाख रु.; द्वितीय किस्त: 30 माह हेतु 2 लाख रु.**; सरकार द्वारा 8% तक ब्याज छूट) (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **पीएम-जनमन योजना (पीएम-जनमन — जनजातीय कार्य मंत्रालय):**

• **शुभारंभ एवं परिव्यय: 15 नवंबर 2023 (जनजातीय गौरव दिवस — भगवान बिरसा मुंडा की जयंती)** को **खूँटी, झारखंड** से **24,104 करोड़ रुपये** (केंद्र अंश: 15,336 करोड़ रु.; राज्य अंश: 8,768 करोड़ रु.) के परिव्यय के साथ प्रारंभ (पीआईबी पीएम-जनमन विज्ञप्ति जुलाई 2026)।

• **लक्ष्य एवं विस्तार: 18 राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह** में निवास करने वाले **75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी — ढेबर आयोग की सिफारिश पर चिह्नित; सर्वाधिक 13 पीवीटीजी ओडिशा में)** को **9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं** (2.39 लाख रु. का पक्का मकान, नल जल, सौर बिजली, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, वन धन विकास केंद्र) से संतृप्त करना (पीआईबी पीएम-जनमन जुलाई 2026)।

• **धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए / प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान — जनजातीय कार्य मंत्रालय):**

• **शुभारंभ एवं परिव्यय: 2 2026 संकलन को हज़ारीबाग (झारखंड)** से **79,156 करोड़ रुपये** (केंद्र अंश: 56,333 करोड़ रु.; राज्य अंश: 22,823 करोड़ रु.) के विशाल परिव्यय के साथ शुभारंभ किया गया (पीआईबी जनजातीय गौरव दिवस विज्ञप्ति नवंबर 2026)।

• **लक्ष्य एवं कवरेज:** देश के **30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 ज़िलों और 2,911 विकासखंडों में स्थित 63,843 जनजातीय-बहुल गाँवों** (जहाँ जनसंख्या ≥ 500 है और अनुसूचित जनजाति आबादी ≥ 50% है) के **5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों** को 5 वर्षों में **17 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों** से लाभान्वित करना (पीआईबी नवंबर 2026 विज्ञप्ति)।

4.3 पेंशन, शिल्पकार एवं जनजातीय कल्याण संतृप्ति प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: यूपीएस द्वारा 25 वर्ष सेवा पर 50% सुनिश्चित पेंशन व 10 वर्ष पर 10,000 रु. न्यूनतम पेंशन

चरण 2
चरण 2: एनपीएस वात्सल्य द्वारा 0-18 वर्ष के नाबालिगों हेतु 1,000 रु./वर्ष से पेंशन कोष निर्माण

चरण 3
चरण 3: पीएम विश्वकर्मा द्वारा 18 पारंपरिक शिल्पों को 15 हज़ार टूलकिट व 5% ब्याज पर 3 लाख रु. ऋण

चरण 4
चरण 4: पीएम-जनमन (75 पीवीटीजी) व धरती आबा अभियान (63,843 गाँव, 79,156 करोड़ रु.) से जनजातीय विकास]`

4.4 पेंशन, शिल्पकार एवं जनजातीय कल्याण योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	शुभारंभ तिथि एवं कुल परिव्यय	मुख्य पात्रता एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत लिंक
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)	वित्त मंत्रालय	24 2026 संकलन को स्वीकृत; **1 अप्रैल 2025 से लागू**	**50% सुनिश्चित पेंशन** (25+ वर्ष सेवा), **60% पारिवारिक पेंशन, 10,000 रु./माह न्यूनतम पेंशन** (10+ वर्ष); सरकारी अंशदान **18.5%**	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
एनपीएस वात्सल्य योजना	वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए	18 2026 संकलन	**0 से 18 वर्ष के सभी नाबालिग**; न्यूनतम **1,000 रु./वर्ष** जमा; 18 वर्ष की आयु पर नियमित एनपीएस प्रथम श्रेणी में रूपांतरण	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम विश्वकर्मा योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)	17 सितंबर 2023; **13,000 करोड़ रु.** (2023–28)	**18 पारंपरिक व्यवसाय**; 500 रु./दिन प्रशिक्षण भत्ता; **15,000 रु. टूलकिट ई-वाउचर; 5% ब्याज पर 3 लाख रु. (1 लाख+2 लाख) ऋण**	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम-जनमन (पीएम-जनमन)	जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय)	15 नवंबर 2023; **24,104 करोड़ रु.**	18 राज्यों व अंडमान-निकोबार के **75 पीवीटीजी समूह**; **9 मंत्रालयों के 11 हस्तक्षेप** (पक्का घर 2.39 लाख रु., सड़क, बिजली)	पीआईबी पीएम-जनमन जुलाई 2026
धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)	जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय)	2 2026 संकलन; **79,156 करोड़ रु.**	30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के **63,843 जनजातीय-बहुल गाँव (5+ करोड़ जनजातीय नागरिक)**; **17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेप**	पीआईबी जनजातीय गौरव दिवस 2026
पीएम मुद्रा योजना ('तरुण प्लस' विस्तार)	वित्त मंत्रालय	8 अप्रैल 2015 (2026 संकलन में विस्तारित)	शिशु (50 हज़ार तक), किशोर (50 हज़ार से 5 लाख), तरुण (5 लाख से 10 लाख) और नया **'तरुण प्लस' (10 लाख रु. से 20 लाख रु. तक)**	केंद्रीय बजट पोर्टल

क्या आप जानते हैं?: केंद्रीय बजट 2024–25 में **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** के अंतर्गत **'तरुण प्लस' (तरुण प्लस)** नामक चौथी श्रेणी जोड़ी गई है, जिसके तहत पूर्व में 'तरुण' श्रेणी (5 से 10 लाख रुपये) का ऋण लेकर सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमियों को **10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक** का ऋण दिया जाता है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **परीक्षा सावधानी बिंदु: पीएम-जनमन (24,104 करोड़ रु.)** केवल **75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)** के लिए **9 मंत्रालयों व 11 हस्तक्षेपों** पर केंद्रित है, जबकि **धरती आबा अभियान / डीएजेजीयूए (79,156 करोड़ रु.) 63,843 सामान्य जनजातीय-बहुल गाँवों (5+ करोड़ आबादी)** के लिए **17 मंत्रालयों व 25 हस्तक्षेपों** पर आधारित है (पीआईबी जुलाई 2026)।

★ **स्मरण सूत्र: एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के 5 मुख्य आंकड़े "50 – 60 – 10 हज़ार – 18.5% – 1/10वाँ"** से याद रखें: **50%** सुनिश्चित पेंशन (25 वर्ष सेवा पर), **60%** पारिवारिक पेंशन, **10,000 रु.** न्यूनतम पेंशन (10 वर्ष पर), **18.5%** सरकारी अंशदान, और प्रत्येक छमाही सेवा पर **1/10वाँ** एकमुश्त भुगतान!

अध्याय 5: उच्च शिक्षा (पीएम विद्यालक्ष्मी व ओएनओएस), युवा रोज़गार पैकेज, कौशल एवं डीप-टेक मिशन

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 5: उच्च शिक्षा (पीएम विद्यालक्ष्मी व ओएनओएस), युवा रोज़गार पैकेज, कौशल एवं डीप-टेक मिशन

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एवं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (शिक्षा मंत्रालय)	**प्रधानमंत्री का रोज़गार एवं कौशल पैकेज (2 लाख करोड़ रु.) तथा अनुसंधान मिशन**	**पीएम विद्यालक्ष्मी एवं युवा रोज़गार पैकेज प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)**

5.1 पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एवं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (शिक्षा मंत्रालय)

• **पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना — 6 2026 संकलन को स्वीकृत, शिक्षा मंत्रालय):**

• **उद्देश्य एवं कुल परिव्यय:** मेधावी छात्रों को आर्थिक अभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न होना पड़े, इस उद्देश्य से **वित्त वर्ष 2026 संकलन–25 से 2030–31 तक 3,600 करोड़ रुपये** के परिव्यय वाली नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की गई है (**पीआईबी पीएम विद्यालक्ष्मी विज्ञप्ति जुलाई 2026**)।

• **लक्षित संस्थान (शीर्ष 860 क्यूएचईआई):** यह योजना एनआईआरएफ स्थान के शीर्ष 100 संस्थानों, राज्य सरकार के शीर्ष 200 उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के सभी संस्थानों सहित देश के **शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई)** में योग्यता के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्रों (प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक छात्रों) पर लागू होती है।

• **पीएम विद्यालक्ष्मी के 3 मुख्य वित्तीय लाभ:**

1. **बिना गारंटी और बिना गिरवी (बिना गिरवी एवं बिना गारंटी) शिक्षा ऋण:** ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से जुड़े समस्त खर्चों के लिए एकीकृत **प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल** के माध्यम से ऋण (**पीआईबी पीएम विद्यालक्ष्मी जुलाई 2026**)।

2. **7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% सरकारी क्रेडिट गारंटी:** बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए **7.5 लाख रुपये तक के बकाया शिक्षा ऋण पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी** देती है।

3. **10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट (पारिवारिक आय ≤ 8 लाख रुपये):** जिन छात्रों की **वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक** है (और जो 4.5 लाख रुपये तक आय वाली पूर्ण ब्याज सब्सिडी योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन केंद्रीय क्षेत्रक ब्याज सब्सिडी में कवर नहीं हैं), उन्हें हर साल 1 लाख छात्रों के लिए मोराटोरियम अवधि के दौरान **10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी (ब्याज सब्सिडी)** ई-वाउचर और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट के माध्यम से दी जाती है (**पीआईबी पीएम विद्यालक्ष्मी जुलाई 2026**)।

• **वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस — 29-न्यायाधीश संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन) को स्वीकृत): 3 कैलेंडर वर्षों (2025, 2026 और 2027) के लिए 6,000 करोड़ रुपये** के आवंटन वाली केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जो यूजीसी के स्वायत्त केंद्र **इनफ्लिबनेट (गांधीनगर)** के माध्यम से 6,300+ सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों के **1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं** को विश्व के 30 प्रमुख प्रकाशकों के **13,000+ अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नलों** तक निःशुल्क डिजिटल पहुँच प्रदान करती है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

5.2 प्रधानमंत्री का रोज़गार एवं कौशल पैकेज (2 लाख करोड़ रु.) तथा अनुसंधान मिशन

• **प्रधानमंत्री का 5 योजनाओं का रोज़गार एवं कौशल पैकेज (5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं हेतु 2 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय):**

• **योजना 1 (रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन योजना-क — प्रथम बार कार्यबल में प्रवेश):** सभी क्षेत्रों में औपचारिक कार्यबल में पहली बार प्रवेश करने वाले और **ईपीएफओ** में पंजीकृत होने वाले युवाओं (वेतन ≤ 1 लाख रु./माह) को **3 किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपये तक एक माह का वेतन**, जिससे **210 लाख युवा** लाभान्वित होंगे (**केंद्रीय बजट पोर्टल**)।

• **योजना 2 (रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन योजना-ख — विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन):** विनिर्माण क्षेत्र में प्रथम बार रोज़गार पाने वाले युवाओं और नियोक्ताओं दोनों को प्रथम 4 वर्षों के ईपीएफओ अंशदान के सापेक्ष प्रत्यक्ष प्रोत्साहन (30 लाख युवाओं को लाभ)।

• **योजना 3 (रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन योजना-ग — नियोक्ताओं को सहायता):** प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति पर नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ अंशदान के लिए **2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की प्रतिपूर्ति** (50 लाख अतिरिक्त रोज़गार प्रोत्साहन)।

• **योजना 4 (1,000 आईटीआई का हब-एंड-स्पोक उन्नयन): 60,000 करोड़ रुपये** के परिव्यय (30,000 करोड़ केंद्र + 20,000 करोड़ राज्य + 10,000 करोड़ उद्योग) से 5 वर्षों में **1,000 सरकारी आईटीआई** (200 हब + 800 स्पोक) का उन्नयन कर **20 लाख युवाओं** को प्रशिक्षित करना (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **योजना 5 (शीर्ष 500 कंपनियों में पीएम इंटर्नशिप योजना — कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय):** देश की **शीर्ष 500 कॉर्पोरेट कंपनियों** (सीएसआर व्यय के आधार पर) में 5 वर्षों में **1 करोड़ युवाओं (आयु 21 से 24 वर्ष)** को **12 माह की इंटर्नशिप**। प्रत्येक प्रशिक्षु को **5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता** (4,500 रु. सरकार द्वारा डीबीटी से + 500 रु. कंपनी के सीएसआर फंड से) तथा आकस्मिक खर्च हेतु **6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान** दिया जाता है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ), इंडिया-एआई (इंडिया-एआई), राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एवं बायो-ई3 नीति:**

• **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ अधिनियम 2023 — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग):** इसके शासी बोर्ड के पदेन **अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री** हैं; वर्ष 2023–28 के लिए **50,000 करोड़ रुपये का कोष** (14,000 करोड़ बजटीय + 36,000 करोड़ निजी/उद्योग क्षेत्र से) तथा बजट 2024–25 में घोषित **1 लाख करोड़ रुपये का निजी अनुसंधान एवं नवाचार वित्तपोषण पूल** (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **इंडिया-एआई मिशन (इंडिया-एआई मिशन — इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय):** 2026 संकलन में **10,371.92 करोड़ रुपये** के परिव्यय से स्वीकृत; इसके तहत **18,000+ जीपीयू**, स्वदेशी फाउंडेशनल एआई आदर्श और **एआई-कोष** डेटासेट प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं।

• **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (डीएसटी): 6,003.65 करोड़ रुपये (2023–2031)** के परिव्यय से **50 से 1,000 भौतिक क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर** विकसित करने हेतु **भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली** में **4 विषयगत केंद्र (विषयगत केंद्र)** स्थापित किए गए हैं।

• **बायो-ई3 नीति (जैव प्रौद्योगिकी विभाग — 2026 संकलन):** अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिए जैव प्रौद्योगिकी (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) के तहत उच्च-प्रदर्शन बायोमैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **केंद्रीय बजट 2026–27 में युवा शक्ति, शिक्षा (1.39 लाख करोड़ रु.), सृजनात्मक अर्थव्यवस्था एवं अर्धचालक मिशन 2.0:**

• **15,000 विद्यालयों एवं 500 महाविद्यालयों में एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स प्रयोगशालाएँ:** भारत की सृजनात्मक ('ऑरेंज') अर्थव्यवस्था को वर्तमान 4.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर **40 अरब डॉलर** करने और **वर्ष 2030 तक 20 लाख नए रोज़गार** सृजित करने हेतु बजट 2026–27 में **15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 उच्च शिक्षण महाविद्यालयों में आधुनिक सृजनात्मक प्रयोगशालाएँ** स्थापित करने की घोषणा की गई (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ एवं 5 विश्वविद्यालय नगर:** बजट 2026–27 में अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत **अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 50,000 करने** और प्रमुख औद्योगिक गलियारों के पास **5 एकीकृत विश्वविद्यालय नगर** स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

• **भारत सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) मिशन 2.0 एवं बायो-फार्मा शक्ति:** स्वदेशी चिप निर्माण, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार हेतु **भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0** तथा भारत को वैश्विक जैव-औषधि निर्माण केंद्र बनाने हेतु **बायो-फार्मा शक्ति** मिशन प्रारंभ किया गया (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

5.3 पीएम विद्यालक्ष्मी एवं युवा रोज़गार पैकेज प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: शीर्ष 860 एनआईआरएफ संस्थानों में प्रवेशित छात्र का प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन

चरण 2
चरण 2: बिना गारंटी ऋण (7.5 लाख तक 75% गारंटी व ≤8 लाख आय पर 10 लाख तक 3% ब्याज छूट)

चरण 3
चरण 3: पीएम इंटर्नशिप योजना द्वारा शीर्ष 500 कंपनियों में प्रशिक्षण (5,000 रु./माह + 6,000 रु.)

चरण 4
चरण 4: ईपीएफओ-संबद्ध रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं क, ख व ग (2 लाख करोड़ रु. पैकेज) से औपचारिक रोज़गार]`

5.4 शिक्षा, कौशल, इंटर्नशिप एवं अनुसंधान योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

योजना / मिशन का नाम	नोडल मंत्रालय / विभाग	कुल परिव्यय एवं अवधि	लक्षित समूह एवं वित्तीय लाभ	आधिकारिक स्रोत लिंक
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना	शिक्षा मंत्रालय	**3,600 करोड़ रु.** (2024–25 से 2030–31)	**860 क्यूएचईआई** के छात्र; बिना गारंटी ऋण; **7.5 लाख तक 75% गारंटी; 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट** (आय ≤ 8 लाख रु.)	पीआईबी पीएम विद्यालक्ष्मी 2026
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)	शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट)	**6,000 करोड़ रु.** (2025–2027)	6,300+ सरकारी संस्थानों के **1.8 करोड़ छात्रों/शोधकर्ताओं** को **13,000+ अंतरराष्ट्रीय जर्नलों** की निःशुल्क पहुँच	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम इंटर्नशिप योजना	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)	2 लाख करोड़ रु. के पैकेज का भाग (5 वर्ष)	**शीर्ष 500 कंपनियों** में **1 करोड़ युवाओं (21–24 वर्ष)** को **5,000 रु./माह भत्ता + 6,000 रु. एकमुश्त अनुदान**	केंद्रीय बजट पोर्टल
1,000 आईटीआई उन्नयन योजना	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	**60,000 करोड़ रु.** (5 वर्ष)	हब-एंड-स्पोक आदर्श पर **1,000 सरकारी आईटीआई** (200 हब + 800 स्पोक) का उन्नयन कर **20 लाख युवाओं** का कौशल विकास	केंद्रीय बजट पोर्टल
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	**50,000 करोड़ रु.** (2023–28) + 1 लाख करोड़ अनुसंधान एवं विकास पूल	शासी बोर्ड के **अध्यक्ष प्रधानमंत्री**; 72% (36,000 करोड़ रु.) निजी व उद्योग स्रोत से	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
इंडिया-एआई मिशन एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन	इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम)	**10,371.92 करोड़ रु.** (इंडिया-एआई) एवं **6,003.65 करोड़ रु.** (राष्ट्रीय क्वांटम मिशन)	इंडिया-एआई में 18,000+ जीपीयू; क्वांटम मिशन में 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान हब व 50–1,000 क्यूबिट कंप्यूटर	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

क्या आप जानते हैं?: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय **4.5 लाख रुपये तक** है और जो तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें पहले से संचालित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन केंद्रीय क्षेत्रक ब्याज सब्सिडी के अंतर्गत मोराटोरियम अवधि के दौरान **100% पूर्ण ब्याज सब्सिडी** मिलती है, जबकि **8 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय** वाले सभी पाठ्यक्रमों के छात्रों को **10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी** मिलती है (पीआईबी पीएम विद्यालक्ष्मी जुलाई 2026)।

• **परीक्षा सावधानी बिंदु: पीएम इंटर्नशिप योजना** का कार्यान्वयन **'कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय' (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय — एमसीए)** द्वारा किया जाता है—न कि कौशल विकास मंत्रालय या श्रम मंत्रालय द्वारा! इसके 5,000 रुपये मासिक भत्ते में **4,500 रुपये केंद्र सरकार** और **500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर फंड** से देती है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

★ **स्मरण सूत्र: पीएम विद्यालक्ष्मी के आंकड़े "860 – 7.5 लाख (75%) – 10 लाख (3% @ ≤8 लाख)"** से याद रखें: **860** शीर्ष संस्थान, **7.5 लाख रु.** तक के ऋण पर **75%** क्रेडिट गारंटी, और **≤ 8 लाख रु.** पारिवारिक आय पर **10 लाख रु.** तक के ऋण पर **3%** ब्याज छूट!

अध्याय 6: कृषि, डिजिटल कृषि मिशन, प्राकृतिक खेती, खाद्य तेल एवं खाद्य सुरक्षा योजनाएँ

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 6: कृषि, डिजिटल कृषि मिशन, प्राकृतिक खेती, खाद्य तेल एवं खाद्य सुरक्षा योजनाएँ

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
डिजिटल कृषि मिशन, प्राकृतिक खेती, तिलहन मिशन एवं क्लीन प्लांट प्रोग्राम

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
डिजिटल कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मूल्य श्रृंखला प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

6.1 डिजिटल कृषि मिशन, प्राकृतिक खेती, तिलहन मिशन एवं क्लीन प्लांट प्रोग्राम

• **डिजिटल कृषि मिशन (2 2026 संकलन को स्वीकृत — कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय):**

• **परिव्यय एवं 3 डिजिटल स्तंभ: 2,817 करोड़ रुपये** (केंद्र अंश: 1,940 करोड़ रु.) के परिव्यय से कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का निर्माण, जिसके **3 मुख्य स्तंभ** हैं:

1. **एग्रीस्टैक (एग्री-स्टैक):** इसमें **किसान रजिस्ट्री (11 करोड़ किसानों को आधार जैसी विशिष्ट 'किसान पहचान पत्र' / किसान पहचान पत्र** जारी करना), **भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र** और **डिजिटल फसल सर्वेक्षण (फसल बुवाई रजिस्ट्री)** शामिल हैं।

2. **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली):** मौसम, मिट्टी, जल और फसल का भू-स्थानिक उपग्रह एकीकरण।

3. **मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण (मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण):** 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि का 1:10,000 पैमाने पर विस्तृत मृदा मानचित्रण (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **भारत-विस्तार डिजिटल कृषि मंच एवं बीज अधिनियम 2026 (केंद्रीय बजट 2026–27):** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए **1.41 लाख करोड़ रुपये** के आवंटन के साथ बजट 2026–27 में डिजिटल कृषि विस्तार हेतु **'भारत-विस्तार'** प्रणाली तथा प्रमाणित एवं जलवायु-अनुकूल बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नया **'बीज अधिनियम 2026'** प्रस्तुत किया गया (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन — 29-न्यायाधीश संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन) को स्वीकृत):** 15वें वित्त आयोग की अवधि (2025–26) तक **2,481 करोड़ रुपये** (केंद्र: 1,584 करोड़ रु.; राज्य: 897 करोड़ रु.) के परिव्यय वाली केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका लक्ष्य ग्राम पंचायतों के भीतर **15,000 समूहों में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि** पर रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर **1 करोड़ किसानों** को जोड़ना, **10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी)** स्थापित करना और **30,000 कृषि सखियों** को तैनात करना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन — 3 2026 संकलन को स्वीकृत):** 7 **वर्षों (2024–25 से 2030–31) के लिए 10,103 करोड़ रुपये** के परिव्यय से प्राथमिक घरेलू तिलहन उत्पादन (सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल) को **39 मिलियन टन (2022–23) से बढ़ाकर 2030–31 तक 69.7 मिलियन टन** करना और घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को **25.45 मिलियन टन** (घरेलू आवश्यकता का 72%) तक पहुँचाना; बीज प्रमाणन और ट्रेसबिलिटी हेतु **'साथी' (साथी) पोर्टल** का उपयोग (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम — 2026 संकलन में स्वीकृत): एशियाई विकास बैंक (एडीबी)** के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा **1,765.67 करोड़ रुपये** के परिव्यय से फलों की फसलों (सेब, अखरोट, बादाम, अंगूर, आम, अनार) के विषाणु-मुक्त पौध सामग्री हेतु देश भर में **9 विश्वस्तरीय क्लीन प्लांट सेंटर (सीपीसी)** स्थापित किए जा रहे हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एवं सहकारी अन्न भंडारण:**

• **पीएम-किसान (पीएम-किसान): 24 फरवरी 2019 (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश)** से प्रारंभ 100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जिसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को **प्रतिवर्ष 6,000 रुपये (2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में)** डीबीटी से दिए जाते हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई — उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय): ब्रिक्स विस्तार चरण (2026 संकलन) से 31 दिसंबर 2028 तक (5 वर्षों के लिए) 11.80 लाख करोड़ रुपये** के अनुमानित परिव्यय पर विस्तारित; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए 2013) के तहत **81.35 करोड़ लाभार्थियों** को निःशुल्क खाद्यान्न (**अंत्योदय अन्न योजना [अंत्योदय अन्न योजना] परिवारों को 35 किग्रा/माह** तथा **प्राथमिकता वाले परिवारों [प्राथमिकता प्राप्त परिवार] को 5 किग्रा प्रति व्यक्ति/माह**) प्रदान करती है (पीआईबी आर्थिक समीक्षा विज्ञप्ति)।

★ **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना (सहकारिता मंत्रालय):** प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (**पैक्स**) के स्तर पर 5 वर्षों में **700 लाख मीस्मरण सूत्र टन (70 एमएमटी)** भंडारण क्षमता का निर्माण तथा 2,516 करोड़ रुपये से **63,000+ कार्यात्मक पैक्स का कंप्यूटरीकरण** (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

6.2 डिजिटल कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मूल्य श्रृंखला प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: एग्रीस्टैक द्वारा 11 करोड़ किसानों को फार्मर आईडी व डिजिटल फसल सर्वेक्षण

चरण 2
चरण 2: पीएम-किसान (6,000 रु./वर्ष), पीएमएफबीवाई (1.5%-5% प्रीमियम) व प्राकृतिक खेती मिशन से उत्पादन

चरण 3
चरण 3: 1 लाख करोड़ रु. एआईएफ एवं पैक्स सहकारी अन्न भंडारण (700 लाख टन) से फसल-पश्चात संरक्षण

चरण 4
चरण 4: पीएमजीकेएवाई द्वारा दिसंबर 2028 तक 81.35 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण]`

6.3 कृषि, सहकारिता एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं की तुलनात्मक सारणी

योजना / मिशन का नाम	नोडल मंत्रालय	कुल परिव्यय एवं समयावधि	मुख्य लक्ष्य एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत लिंक
डिजिटल कृषि मिशन	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	**2,817 करोड़ रु.** (2026 संकलन में स्वीकृत)	**एग्रीस्टैक (11 करोड़ फार्मर आईडी), कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली** और 14.2 करोड़ हेक्टेयर मृदा मानचित्रण	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	**2,481 करोड़ रु.** (2026 संकलन में स्वीकृत)	**7.5 लाख हेक्टेयर** में **1 करोड़ किसान**; **10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी)** व 30,000 कृषि सखी	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	**10,103 करोड़ रु.** (2024–25 से 2030–31)	तिलहन उत्पादन **39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030–31 तक 69.7 मिलियन टन** करना; बीज ट्रेसबिलिटी हेतु **साथी पोर्टल**	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम)	कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)	**1,765.67 करोड़ रु.** (एडीबी के सहयोग से)	विषाणु-मुक्त बागवानी पौध सामग्री हेतु देश में **9 क्लीन प्लांट सेंटर (सीपीसी)** की स्थापना	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	24 फरवरी 2019 (100% केंद्रीय क्षेत्रक)	सभी भूमिधारक किसान परिवारों को **6,000 रुपये/वर्ष** (2,000 रु. की 3 किस्तें)	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	**11.80 लाख करोड़ रु.** (2026 संकलन – दिसंबर 2028)	**81.35 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों** को मुफ़्त अनाज (**अंत्योदय अन्न योजना: 35 किग्रा/परिवार; प्राथमिकता प्राप्त परिवार: 5 किग्रा/व्यक्ति**)	पीआईबी आर्थिक समीक्षा विज्ञप्ति

क्या आप जानते हैं?: रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग बढ़ाने के लिए शुरू की गई **'पीएम-प्रणाम' (प्रधानमंत्री प्रणाम)** योजना का कोई अलग बजट नहीं है; इसके तहत जो राज्य अपने पिछले 3 वर्षों के औसत की तुलना में रासायनिक उर्वरक खपत कम करके सब्सिडी बचाते हैं, केंद्र सरकार उस **बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% हिस्सा उस राज्य को अनुदान** के रूप में वापस देती है! साथ ही मिट्टी में सल्फर की कमी दूर करने के लिए **'यूरिया गोल्ड' (यूरिया गोल्ड — 37% नाइट्रोजन + 17% सल्फर लेपित यूरिया)** शुभारंभ किया गया (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **परीक्षा सावधानी बिंदु:** 2026 संकलन में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्रालय की सभी 18 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाकर **1,01,321.61 करोड़ रुपये** की केवल **2 छत्र योजनाओं (छत्र योजनाएँ)** में समाहित कर दिया है: (1) **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना — 57,074.72 करोड़ रु.)** और (2) **कृषोन्नति योजना (कृषोन्नति योजना — 44,246.89 करोड़ रु.)** (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

★ **स्मरण सूत्र: पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की प्रीमियम दरें "रबी 1.5% – खरीफ 2% – बागवानी/वाणिज्यिक 5%"** से याद रखें!

अध्याय 7: 108 प्रमुख केंद्रीय सरकारी योजनाओं की मंत्रालय-वार संपूर्ण संदर्भ सारणी (1 से 108)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 7: 108 प्रमुख केंद्रीय सरकारी योजनाओं की मंत्रालय-वार संपूर्ण संदर्भ सारणी (1 से 108)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
केंद्रीय क्षेत्रक (केंद्रीय क्षेत्रक) बनाम केंद्र प्रायोजित योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजना) की वित्तीय संरचना

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
केंद्रीय क्षेत्रक बनाम केंद्र प्रायोजित योजना निधि प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
भारत सरकार की 108 प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण मंत्रालय-वार संपूर्ण संदर्भ सारणी (योजना 1 से 108)

7.1 केंद्रीय क्षेत्रक (केंद्रीय क्षेत्रक) बनाम केंद्र प्रायोजित योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजना) की वित्तीय संरचना

• **केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ (केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ):** इनका **100% वित्तपोषण केंद्र सरकार** द्वारा भारत की संचित निधि से किया जाता है और इनका कार्यान्वयन केंद्रीय तंत्र द्वारा संघ सूची के विषयों पर होता है (उदाहरण: पीएम-किसान, पीएम सूर्य घर, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, पीएम विद्यालक्ष्मी, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, अग्निपथ, नमामि गंगे, भारतनेट) (केंद्रीय बजट विवरण 4-ख)।

• **केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (केंद्र प्रायोजित योजनाएँ — केंद्र प्रायोजित योजना):** इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केंद्र व राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात **सामान्य राज्यों के लिए 60:40, 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं 3 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर) के लिए 90:10**, तथा **बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%** होता है (नीति आयोग)।

7.2 केंद्रीय क्षेत्रक बनाम केंद्र प्रायोजित योजना निधि प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: केंद्रीय बजट में केंद्रीय क्षेत्रक (विवरण 4-ख) व केंद्र प्रायोजित (विवरण 4-क) आवंटन

चरण 2
चरण 2: केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं में 100% केंद्र सरकार का बजट (पीएम-किसान, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा)

चरण 3
चरण 3: केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 60:40 (सामान्य राज्य) व 90:10 (पूर्वोत्तर/हिमालयी) अनुपात

चरण 4
चरण 4: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एवं एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श द्वारा वास्तविक समय में लाभार्थियों के खातों में डीबीटी हस्तांतरण]`

7.3 भारत सरकार की 108 प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण मंत्रालय-वार संपूर्ण संदर्भ सारणी (योजना 1 से 108)

क्र.	योजना का नाम	नोडल केंद्रीय मंत्रालय	शुभारंभ / संशोधन वर्ष	मुख्य उद्देश्य, लक्षित वर्ग एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
1	पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)	वित्त मंत्रालय	28 अगस्त 2014 (2026 संकलन में 10 वर्ष पूर्ण)	शून्य-बैलेंस बैंक खाते; **10,000 रु. ओवरड्राफ्ट; 2 लाख रु. रूपे दुर्घटना बीमा**; 53.1+ करोड़ खाते (55.6% महिलाएँ)	पीआईबी
2	पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	वित्त मंत्रालय	9 मई 2015	**18–50 वर्ष** आयु वर्ग हेतु **436 रु./वर्ष** प्रीमियम पर **2 लाख रुपये** का जीवन बीमा कवर	पीआईबी
3	पीएम सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	वित्त मंत्रालय	9 मई 2015	**18–70 वर्ष** आयु वर्ग हेतु **20 रु./वर्ष** प्रीमियम पर **2 लाख रुपये** (आंशिक अपंगता पर 1 लाख रु.) का दुर्घटना बीमा	पीआईबी
4	अटल पेंशन योजना (अटल पेंशन योजना)	वित्त मंत्रालय (पीएफआरडीए)	9 मई 2015	असंगठित क्षेत्र के कामगारों (**18–40 वर्ष**, गैर-आयकरदाता) को 60 वर्ष की आयु पर **1,000 रु. से 5,000 रु./माह** गारंटीकृत पेंशन	पीआईबी
5	पीएम मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	वित्त मंत्रालय	8 अप्रैल 2015 (2026 संकलन में विस्तार)	बिना गारंटी सूक्ष्म उद्यम ऋण: शिशु (≤50 हज़ार), किशोर (50 हज़ार से 5 लाख), तरुण (5 लाख से 10 लाख) एवं नया **तरुण प्लस (10 लाख से 20 लाख)**	केंद्रीय बजट
6	स्टैंड-अप इंडिया योजना	वित्त मंत्रालय	5 अप्रैल 2016 (2025 तक विस्तारित)	प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम **1 अनुसूचित जाति/जनजाति और 1 महिला उद्यमी** को ग्रीनफील्ड उद्यम हेतु **10 लाख रु. से 1 करोड़ रु.** का ऋण	पीआईबी
7	एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)	वित्त मंत्रालय	2026 संकलन स्वीकृत (**1 अप्रैल 2025 से लागू**)	25+ वर्ष सेवा पर **50% सुनिश्चित पेंशन**, **60% पारिवारिक पेंशन**, 10+ वर्ष पर **10,000 रु. न्यूनतम पेंशन**, **18.5% सरकारी अंशदान**	पीआईबी
8	एनपीएस वात्सल्य योजना (एनपीएस वात्सल्य)	वित्त मंत्रालय (पीएफआरडीए)	18 2026 संकलन	**0–18 वर्ष के नाबालिगों** हेतु पेंशन खाता; न्यूनतम **1,000 रु./वर्ष** जमा; 18 वर्ष पर नियमित एनपीएस प्रथम श्रेणी में रूपांतरण	पीआईबी

क्र.	योजना का नाम	नोडल केंद्रीय मंत्रालय	शुभारंभ / संशोधन वर्ष	मुख्य उद्देश्य, लक्षित वर्ग एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
9	महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र	वित्त मंत्रालय	1 अप्रैल 2023 (2023–25)	महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए **7.5% निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज** पर 2 वर्ष के लिए **2 लाख रुपये** तक की जमा योजना	केंद्रीय बजट
10	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना)	वित्त मंत्रालय	2023 में सीमा दोगुनी	वरिष्ठ नागरिकों हेतु अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से दोगुनी कर **30 लाख रुपये** की गई (8.2% ब्याज दर)	केंद्रीय बजट
11	पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	24 फरवरी 2019	सभी भूमिधारक किसान परिवारों को **6,000 रु./वर्ष** (2,000 रु. की 3 किस्तों में) डीबीटी द्वारा प्रत्यक्ष अंतरण	पीआईबी
12	पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	18 फरवरी 2016	किसानों के लिए प्रीमियम: **रबी (1.5%), खरीफ (2%) और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों (5%)**	पीआईबी
13	पीएम कृषि सिंचाई योजना (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)	कृषि एवं जल शक्ति मंत्रालय	1 जुलाई 2015	हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप (सूक्ष्म सिंचाई — ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	पीआईबी
14	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (मृदा स्वास्थ्य कार्ड)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	19 फरवरी 2015 (सूरतगढ़, राजस्थान)	मिट्टी के **12 मानकों** (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश; गंधक (सल्फर); जस्ता, लौह, तांबा, मैंगनीज, बोरॉन; तथा पीएच मान, विद्युत चालकता, जैविक कार्बन) की जांच कर उर्वरक अनुशंसा	पीआईबी
15	ई-नाम (ई-नाम) राष्ट्रीय कृषि बाज़ार	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	14 अप्रैल 2016	**लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ** द्वारा संचालित अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, जिससे **1,389+ कृषि उपज विपणन समिति मंडियाँ** जुड़ी हैं	पीआईबी
16	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	जुलाई 2020 (2026 संकलन में विस्तार)	**1 लाख करोड़ रुपये** का कोष (2020–33); 2 करोड़ रु. तक के ऋण पर **3% ब्याज छूट** व सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी कोष ट्रस्ट क्रेडिट गारंटी	केंद्रीय बजट
17	नमो ड्रोन दीदी योजना	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	नवंबर 2023 (**1,261 करोड़ रु.**)	**15,000 महिला एसएचजी** को कृषि ड्रोन खरीद पर **80% सब्सिडी (अधिकतम 8 लाख रु.)**	पीआईबी
18	डिजिटल कृषि मिशन	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2 2026 संकलन (**2,817 करोड़ रु.**)	**एग्रीस्टैक (11 करोड़ फार्मर आईडी), कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली** और 14.2 करोड़ हेक्टेयर मृदा प्रोफ़ाइल मैपिंग	पीआईबी
19	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	29-न्यायाधीश संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन) (**2,481 करोड़ रु.**)	7.5 लाख हेक्टेयर में **1 करोड़ किसान** एवं **10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी)**	पीआईबी
20	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन एवं पाम ऑयल)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2026 संकलन (**10,103 करोड़ रु.** तिलहन)	2030–31 तक तिलहन उत्पादन **69.7 मिलियन टन** करना; ऑयल पाम मिशन (11,040 करोड़ रु.) से पूर्वोत्तर व अंडमान में विस्तार	पीआईबी
21	क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2026 संकलन (**1,765.67 करोड़ रु.**)	एडीबी के सहयोग से विषाणु-मुक्त बागवानी पौध हेतु **9 क्लीन प्लांट सेंटर (सीपीसी)** की स्थापना	पीआईबी
22	पीएम किसान मानधन योजना (प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	12 सितंबर 2019 (राँची)	लघु एवं सीमांत किसानों (**18–40 वर्ष**) को 60 वर्ष की आयु होने पर **3,000 रुपये/माह** की पेंशन	पीआईबी
23	पीएम-आरकेवीवाई एवं कृषोन्नति योजना	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2026 संकलन (**1,01,321 करोड़ रु.**)	18 कृषि योजनाओं का 2 छत्र योजनाओं में विलय: **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (57,074 करोड़ रु.)** व **कृषोन्नति (44,246 करोड़ रु.)**	पीआईबी
24	पीएम मत्स्य संपदा योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	मई 2020 (**20,050 करोड़ रु.**)	नीली क्रांति; 2026 संकलन में **पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना — 6,000 करोड़ रु.)** जुड़ी	पीआईबी

क्र.	योजना का नाम	नोडल केंद्रीय मंत्रालय	शुभारंभ / संशोधन वर्ष	मुख्य उद्देश्य, लक्षित वर्ग एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
25	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (राष्ट्रीय पशुधन मिशन)	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	2026 संकलन में संशोधित	घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट संरक्षण व चारा बीज प्रसंस्करण हेतु **50% पूंजीगत सब्सिडी (50 लाख रु. तक)**	पीआईबी
26	मनरेगा (मनरेगा)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	अधिनियम 2005 (2 फरवरी 2006 से लागू)	ग्रामीण परिवारों को **100 दिन** अकुशल रोज़गार की कानूनी गारंटी; कम से कम **1/3 (33%) महिला लाभार्थी** अनिवार्य	केंद्रीय बजट
27	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय	जून 2011 (आजीविका)	**10 करोड़+ ग्रामीण महिलाओं** को **90 लाख+ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)** से जोड़ा गया	पीआईबी
28	लखपति दीदी पहल	ग्रामीण विकास मंत्रालय	अगस्त 2023 (2026 संकलन में लक्ष्य विस्तार)	**3 करोड़ एसएचजी महिलाओं** को न्यूनतम **1,00,000 रुपये वार्षिक शुद्ध आय** तक पहुँचाना	पीआईबी नवंबर 2026
29	पीएम आवास योजना – ग्रामीण (विस्तार)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	20 नवंबर 2016 (विस्तार: 2026 संकलन)	2024–29 में **2 करोड़ नए ग्रामीण घर (3,06,137 करोड़ रु.)**; मैदानी **1.20 लाख रु.** व पहाड़ी **1.30 लाख रु.**	पीआईबी नवंबर 2026
30	पीएम ग्राम सड़क योजना – चरण चतुर्थ	ग्रामीण विकास मंत्रालय	2026 संकलन स्वीकृत (**70,125 करोड़ रु.**)	2024–29 में **25,000 बसावटों** को जोड़ने हेतु **62,500 किमी बारहमासी ग्रामीण सड़कों** का निर्माण	पीआईबी
31	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	15 अगस्त 1995	बीपीएल परिवारों के वृद्धों, विधवाओं व दिव्यांगों को पेंशन तथा **अन्नपूर्णा योजना** (10 किग्रा मुफ़्त अनाज)	पीआईबी
32	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय	फरवरी 2016	"गाँव की आत्मा, शहर की सुविधाएँ" के सिद्धांत पर **300 ग्रामीण विकास केंद्रों** का विकास	पीआईबी
33	पीएम आवास योजना – शहरी 2.0	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	25 जून 2015 (2.0: 2026 संकलन)	2024–29 में **1 करोड़ शहरी आवास (10 लाख करोड़ रु. निवेश**, 2.30 लाख करोड़ रु. केंद्रीय सहायता)	पीआईबी
34	पीएम स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्वनिधि)	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1 जून 2020	शहरी पथ विक्रेताओं (पथ विक्रेता) को 3 किस्तों में बिना गारंटी ऋण: **10,000 रु. → 20,000 रु. → 50,000 रु.** (+ 7% ब्याज सब्सिडी)	पीआईबी
35	स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत 2.0 (अमृत 2.0)	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	25 जून 2015 (अमृत 2.0: 2021)	100 स्मार्ट शहर; **अमृत 2.0 (2.99 लाख करोड़ रु.)** द्वारा सभी **4,700+ वैधानिक कस्बों** में 100% नल जल आपूर्ति	पीआईबी
36	स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1 अक्टूबर 2021 (**1.41 लाख करोड़ रु.**)	कचरा-मुक्त शहर, अपशिष्ट पृथक्करण, पुराने कचरे के पहाड़ों का बायो-रेमेडिएशन एवं खुले में शौच मुक्त+/खुले में शौच मुक्त++/जल+ प्रमाणन	पीआईबी
37	पीएम-ईबस सेवा (प्रधानमंत्री ई-बस सेवा)	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	अगस्त 2023 (**57,613 करोड़ रु.**)	पीपीपी आदर्श पर **169 शहरों** में **10,000 इलेक्ट्रिक सूत्र बसों** का संचालन एवं भुगतान सुरक्षा तंत्र (3,435 करोड़ रु., 2026 संकलन)	पीआईबी
38	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सितंबर 2013	शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण, शहरी एसएचजी ऋण और शहरी बेघरों हेतु चौबीसों घंटे आश्रय गृह	पीआईबी
39	आयुष्मान भारत पीएम-जय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	23 सितंबर 2018 (राँची)	**प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये** का कैशलेस अस्पताल उपचार कवर; **55 करोड़+ लाभार्थी**	पीआईबी
40	आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	29 2026 संकलन	**70+ वर्ष के सभी वरिष्ठ नागरिकों** को (आय सीमा मुक्त) **5 लाख रु./वर्ष** का स्वास्थ्य कवर (**6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक**)	पीआईबी अक्टूबर 2026
41	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	27 सितंबर 2021	नागरिकों को **14-अंकीय आभा आईडी** तथा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड इकोसिस्टम प्रदान करना	पीआईबी

क्र.	योजना का नाम	नोडल केंद्रीय मंत्रालय	शुभारंभ / संशोधन वर्ष	मुख्य उद्देश्य, लक्षित वर्ग एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
42	पीएम-अभीम (प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	25 अक्टूबर 2021 (**64,180 करोड़ रु.**)	पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन — क्रिटिकल केयर ब्लॉक एवं एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण	पीआईबी
43	राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन	स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय	1 जुलाई 2023 (शहडोल, मध्य प्रदेश)	वर्ष **2047** तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन हेतु 17 राज्यों के 278 ज़िलों में 7 **करोड़ लोगों की जांच**	पीआईबी
44	मिशन इंद्रधनुष एवं यू-विन पोर्टल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	25 दिसंबर 2014 (यू-विन: 2024)	बच्चों व गर्भवती महिलाओं का **12 टीकों** द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण एवं **यू-विन** पर डिजिटल ट्रैकिंग	पीआईबी
45	जननी सुरक्षा योजना (जननी सुरक्षा योजना) एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	अप्रैल 2005 / जून 2011	संस्थागत प्रसव हेतु नकद प्रोत्साहन (जननी सुरक्षा योजना) तथा गर्भवती महिलाओं व नवजातों को 100% निःशुल्क प्रसव व उपचार (जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम)	पीआईबी
46	निक्षय पोषण योजना (टीबी मुक्त भारत)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	अप्रैल 2018 (2026 संकलन में दोगुनी)	सभी टीबी (टीबी) रोगियों को पोषण सहायता राशि 500 रु. से दोगुनी कर **1,000 रुपये प्रतिमाह** की गई	पीआईबी
47	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2021–2026 (**1.81 लाख करोड़ रु.**)	0–6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों (14–18 वर्ष) व गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण एवं एनीमिया का उन्मूलन	पीआईबी
48	मिशन शक्ति (संबल एवं सामर्थ्य)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2021–2026 (**20,989 करोड़ रु.**)	**संबल** (वन स्टॉप सेंटर, 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत) एवं **सामर्थ्य** (पीएमएमवीवाई, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास)	पीआईबी
49	पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1 जनवरी 2017 (2022 में संशोधित)	प्रथम संतान पर **5,000 रु.** तथा दूसरी संतान **बालिका होने पर 6,000 रु.** की मातृत्व सहायता	पीआईबी
50	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ)	महिला, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय	22 जनवरी 2015 (पानीपत, हरियाणा)	जन्म के समय लिंगानुपात (जन्म के समय लिंगानुपात) में प्रतिवर्ष 2 अंकों का सुधार और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा	पीआईबी
51	मिशन वात्सल्य	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	बाल संरक्षण योजना का नया रूप	किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, **चाइल्डलाइन (1098 का 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली में विलय)** व 4,000 रु./माह स्पॉन्सरशिप	पीआईबी
52	पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	29 मई 2021	कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु पर **10 लाख रुपये** का कोष व उच्च शिक्षा सहायता	पीआईबी
53	पीएम विद्यालक्ष्मी योजना	शिक्षा मंत्रालय	6 2026 संकलन (**3,600 करोड़ रु.**)	**860 क्यूएचईआई** में बिना गारंटी ऋण; **7.5 लाख तक 75% गारंटी**; **10 लाख तक 3% ब्याज छूट** (पारिवारिक आय ≤ 8 लाख रु.)	पीआईबी जुलाई 2026
54	वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)	शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट)	29-न्यायाधीश संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन) (**6,000 करोड़ रु.**)	**1.8 करोड़ छात्रों/शिक्षकों** को **13,000+ अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नलों** की निःशुल्क डिजिटल पहुँच (2025–27)	पीआईबी
55	पीएम श्री स्कूल (प्रधानमंत्री श्री विद्यालय)	शिक्षा मंत्रालय	5 सितंबर 2022 (**27,360 करोड़ रु.**)	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (5+3+3+4)** की प्रयोगशाला के रूप में **14,500+ स्कूलों** का हरित व स्मार्ट उन्नयन	पीआईबी
56	पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण — मिड-डे मील)	शिक्षा मंत्रालय	सितंबर 2021 (**1.30 लाख करोड़ रु.**)	सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में **बालवाटिका (प्री-प्राइमरी) और कक्षा 1 से 8** तक के बच्चों को गर्म पका भोजन	पीआईबी
57	समग्र शिक्षा अभियान 2.0	शिक्षा मंत्रालय	2018 (2026 तक विस्तारित)	**सर्व शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) और शिक्षक शिक्षा (शिक्षक शिक्षा)** का प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक एकीकरण	पीआईबी

क्र.	योजना का नाम	नोडल केंद्रीय मंत्रालय	शुभारंभ / संशोधन वर्ष	मुख्य उद्देश्य, लक्षित वर्ग एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
58	पीएम-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान — पूर्व में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान)	शिक्षा मंत्रालय	जून 2023 (**12,929.16 करोड़ रु.**)	राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बहु-विषयक शिक्षा व राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद प्रत्यायन हेतु वित्तीय सहायता	पीआईबी
59	निपुण भारत मिशन (निपुण भारत)	शिक्षा मंत्रालय	5 जुलाई 2021	प्रत्येक बच्चे को **कक्षा 3 के अंत तक** मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (**बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान**) में दक्ष बनाना	पीआईबी
60	उल्लास (उल्लास — नव भारत साक्षरता कार्यक्रम)	शिक्षा मंत्रालय	2022–2027 (**1,037.90 करोड़ रु.**)	**15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 5 करोड़ निरक्षरों** को बुनियादी साक्षरता और डिजिटल/वित्तीय कौशल प्रदान करना	पीआईबी
61	पीएम-युवा 2.0 (प्रधानमंत्री युवा 2.0)	शिक्षा मंत्रालय (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास)	अक्टूबर 2022	**30 वर्ष से कम आयु** के युवा लेखकों को 6 माह तक **50,000 रुपये/माह** की छात्रवृत्ति व मेंटरशिप	पीआईबी
62	पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	13 2026 संकलन (**75,021 करोड़ रु.**)	**1 करोड़ घरों** में रूफशीर्ष सोलर, **300 यूनिट मुफ़्त बिजली/माह** और अधिकतम **78,000 रु.** सब्सिडी	पीआईबी मार्च 2026
63	पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम)	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	मार्च 2019 (**34,422 करोड़ रु.**)	किसानों के लिए सौर पंप व सौर संयंत्र स्थापित कर **30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता** का सृजन	पीआईबी
64	राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	4 जनवरी 2023 (**19,744 करोड़ रु.**)	वर्ष 2030 तक **5 एमएमटी प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन** एवं 125 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता	पीआईबी
65	पीएम-जनमन (पीएम-जनमन)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	15 नवंबर 2023 (**24,104 करोड़ रु.**)	18 राज्यों व अंडमान के 75 **पीवीटीजी समूहों** के लिए **9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 बुनियादी सुविधाएँ**	पीआईबी जुलाई 2026
66	धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2 2026 संकलन (**79,156 करोड़ रु.**)	**63,843 जनजातीय-बहुल गाँवों (5+ करोड़ आबादी)** में **17 मंत्रालयों द्वारा 25 हस्तक्षेप**	पीआईबी नवंबर 2026
67	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	संशोधित (**740 विद्यालय लक्ष्य**)	**>50% अनुसूचित जनजाति आबादी और ≥20,000 जनजातीय जनसंख्या** वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा संचालित)	पीआईबी
68	पीएम विश्वकर्मा योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	17 सितंबर 2023 (**13,000 करोड़ रु.**)	**18 पारंपरिक शिल्पों** को 15,000 रु. टूलकिट ई-वाउचर एवं **5% ब्याज पर 3 लाख रु. (1 लाख+2 लाख) ऋण**	पीआईबी
69	रैंप योजना एवं प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	रैंप (2022–26, **6,062.45 करोड़ रु.**)	विश्व बैंक समर्थित **रैंप** योजना; **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम** में विनिर्माण हेतु 50 लाख व सेवा हेतु 20 लाख तक 15%–35% सब्सिडी	पीआईबी
70	पीएम-यशस्वी एवं श्रेष्ठ (श्रेष्ठ)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2021–2026	**प्रधानमंत्री यशस्वी** (ओबीसी/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति छात्रों हेतु छात्रवृत्ति); **श्रेष्ठ** (मेधावी अनुसूचित जाति छात्रों हेतु श्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों में शिक्षा)	पीआईबी
71	नमस्ते (नमस्ते) एवं स्माइल (स्माइल)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2023 / 2022	**नमस्ते** (सीवर/सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई — सामाजिक न्याय मंत्रालय + आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय); **स्माइल** (ट्रांसजेंडर व भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का पुनर्वास)	पीआईबी
72	पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2021–2026	अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) बहुल गाँवों को **'आदर्श ग्राम'** के रूप में विकसित करना व छात्रावास निर्माण	पीआईबी
73	पीएम-दक्ष एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2020 / 2017	**प्रधानमंत्री दक्ष** (अनुसूचित जाति/ओबीसी/सफाई कर्मचारियों को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण); **राष्ट्रीय वयोश्री** (बीपीएल बुजुर्गों को नि:शुल्क सहायक उपकरण)	पीआईबी

क्र.	योजना का नाम	नोडल केंद्रीय मंत्रालय	शुभारंभ / संशोधन वर्ष	मुख्य उद्देश्य, लक्षित वर्ग एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
74	जल जीवन मिशन (हर घर जल)	जल शक्ति मंत्रालय	15 अगस्त 2019 (**3.60 लाख करोड़ रु.**)	प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से **55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)** शुद्ध पेयजल	पीआईबी
75	स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण चरण द्वितीय	जल शक्ति मंत्रालय	2020–2025 (**1.40 लाख करोड़ रु.**)	सभी गाँवों को ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ **खुले में शौच मुक्त प्लस (आकांक्षी, उदीयमान व उत्कृष्ट श्रेणी)** बनाना	पीआईबी
76	नमामि गंगे 2.0 एवं अटल भूजल योजना	जल शक्ति मंत्रालय	नमामि गंगे 2026 तक (**22,500 करोड़ रु.**)	गंगा एवं सहायक नदियों का संरक्षण (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन); **अटल भूजल (6,000 करोड़ रु.)** द्वारा 7 राज्यों में भूजल सुधार	पीआईबी
77	पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	दिसंबर 2028 तक विस्तारित (**11.80 लाख करोड़ रु.**)	**81.35 करोड़ लाभार्थियों** को मुफ़्त अनाज + **वन नेशन वन राशन कार्ड (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड)** पोर्टेबिलिटी	पीआईबी
78	पीएम उज्ज्वला योजना (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1 मई 2016 (बलिया, उत्तर प्रदेश)	**10.35 करोड़ महिलाओं** को मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन तथा **300 रुपये प्रति सिलेंडर** (वर्ष में 12 सिलेंडर तक) लक्षित सब्सिडी	पीआईबी
79	सतत (सतत) एवं गोबरधन (गोबरधन)	पेट्रोलियम एवं जल शक्ति मंत्रालय	2018	**सतत** के तहत 5,000 कंप्रेस्ड बायो-गैस (संपीड़ित बायो-गैस) संयंत्र; **गोबरधन** द्वारा गोबर व जैविक कचरे से बायोगैस निर्माण	पीआईबी
80	पीएम ई-ड्राइव एवं उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन ऑटो / बैटरी	भारी उद्योग मंत्रालय	2026 संकलन (**10,900 करोड़ रु.**)	इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन; उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन ऑटो (25,938 करोड़ रु.) व उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन उन्नत रसायन सेल बैटरी (18,100 करोड़ रु.)	पीआईबी
81	उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन — 14 क्षेत्र)	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं संबंधित मंत्रालय	2020 से (**1.97 लाख करोड़ रु.**)	**14 विनिर्माण क्षेत्रों** (मोबाइल, फार्मा, टेलीकॉम, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, स्टील, ड्रोन आदि) में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा	नीति आयोग
82	पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय वृहद कार्ययोजना	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)	13 अक्टूबर 2021	**7 इंजनों** (सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स) और 16 मंत्रालयों का भौगोलिक सूचना प्रणाली डिजिटल मंच	पीआईबी
83	स्टार्टअप इंडिया एवं फंड ऑफ फंड्स	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)	16 जनवरी 2016	**1.49 लाख+ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग मान्यता प्राप्त स्टार्टअप**; 10,000 करोड़ रु. फंड ऑफ फंड्स व **एंजेल टैक्स की 100% समाप्ति (2026 संकलन)**	पीआईबी 2026 संकलन
84	पीएम मित्र पार्क (प्रधानमंत्री मित्र पार्क)	वस्त्र मंत्रालय (वस्त्र मंत्रालय)	अक्टूबर 2021 (**4,445 करोड़ रु.**)	**तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र** में 7 **एकीकृत वस्त्र पार्क**	पीआईबी
85	पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	2008 (2015 में पुनर्गठित)	**25,000 जनऔषधि केंद्रों** के लक्ष्य के साथ बाज़ार मूल्य से **50% से 90% सस्ती जेनेरिक दवाएँ**	पीआईबी
86	पीएम-प्रणाम एवं यूरिया गोल्ड	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	जून 2023 (**3.70 लाख करोड़ रु.** पैकेज)	रासायनिक उर्वरक घटाने वाले राज्यों को **बचाई गई सब्सिडी का 50% अनुदान**; सल्फर-लेपित **यूरिया गोल्ड** शुभारंभ	पीआईबी
87	पीएम कौशल विकास योजना 4.0 एवं एसआईडीएच	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (2022–26)	एआई, रोबोटिक्स, त्रि-आयामी (3डी) प्रिंटिंग और ड्रोन में आधुनिक प्रशिक्षण तथा **स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच)**	पीआईबी
88	1,000 आईटीआई का उन्नयन (हब-एंड-स्पोक)	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	बजट 2024–25 (**60,000 करोड़ रु.**)	5 वर्षों में **1,000 सरकारी आईटीआई** (200 हब + 800 स्पोक) का उन्नयन कर **20 लाख युवाओं** को प्रशिक्षण	केंद्रीय बजट
89	रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन (रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन योजना क, ख, ग)	श्रम और रोज़गार मंत्रालय	बजट 2024–25 (**1.07 लाख करोड़ रु.**)	**ईपीएफओ से जुड़ी 3 योजनाएँ**—प्रथम बार नौकरी पाने वालों, विनिर्माण क्षेत्र और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन	केंद्रीय बजट

क्र.	योजना का नाम	नोडल केंद्रीय मंत्रालय	शुभारंभ / संशोधन वर्ष	मुख्य उद्देश्य, लक्षित वर्ग एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
90	ई-श्रम पोर्टल एवं पीएम-श्रम योगी मानधन	श्रम और रोज़गार मंत्रालय	ई-श्रम (अगस्त 2021) / प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (2019)	**30 करोड़+ असंगठित श्रमिक** पंजीकृत (12-अंकीय सार्वभौमिक खाता संख्या); **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन** में 60 वर्ष की आयु पर **3,000 रु./माह पेंशन**	पीआईबी
91	पीएम इंटर्नशिप योजना (शीर्ष 500 कंपनियाँ)	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)	2026 संकलन	**1 करोड़ युवाओं (21–24 वर्ष)** को **5,000 रु./माह भत्ता** + **6,000 रु. एकमुश्त अनुदान** के साथ 12 माह की इंटर्नशिप	केंद्रीय बजट
92	भारतमाला, पर्वतमाला एवं उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)	सड़क परिवहन एवं नागर विमानन मंत्रालय	2017 / 2022 / 2016	**भारतमाला** (राजमार्ग), **पर्वतमाला** (राष्ट्रीय रोपवे विकास) और **उड़ान** (उड़े देश का आम नागरिक — 10 वर्ष के लिए विस्तारित)	पीआईबी
93	सागरमाला एवं हरित नौका पहल	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	मार्च 2015 / 2023	7,516 किमी तटरेखा पर बंदरगाह-आधारित विकास, **111 राष्ट्रीय जलमार्ग** और हरित अंतर्देशीय जलयान	पीआईबी
94	अमृत भारत स्टेशन योजना एवं कवच	रेल मंत्रालय	2022–2023	**1,309+ रेलवे स्टेशनों** का पुनर्विकास और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली **'कवच' (सुरक्षा अखंडता स्तर-4)** की तैनाती	पीआईबी
95	भारतनेट चरण-तृतीय एवं सेमीकॉन इंडिया	संचार मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय	भारतनेट-तृतीय **(1.39 लाख करोड़ रु.)**	6.40 लाख गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर; **सेमीकॉन इंडिया (76,000 करोड़ रु.)** के तहत सेमीकंडक्टर फैब्स को 50% वित्तीय सहायता	पीआईबी
96	इंडिया-एआई मिशन (इंडिया-एआई मिशन)	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2026 संकलन **(10,371.92 करोड़ रु.)**	**18,000+ जीपीयू** की तैनाती, स्वदेशी एआई आदर्श और **एआई-कोष** डेटासेट प्लेटफॉर्म	पीआईबी
97	अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	2023 (**50,000 करोड़ रु.** व **6,003.65 करोड़ रु.**)	विश्वविद्यालय अनुसंधान हेतु **एएनआरएफ**; क्वांटम कंप्यूटिंग हेतु 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान हब **(राष्ट्रीय क्वांटम मिशन)**	पीआईबी
98	बायो-ई3 नीति एवं विज्ञान धारा योजना	जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं डीएसटी	2026 संकलन **(विज्ञान धारा: 10,579 करोड़ रु.)**	**बायो-ई3** द्वारा बायोमैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा; **विज्ञान धारा** में डीएसटी की 3 छत्र योजनाओं का एकीकरण	पीआईबी
99	मिशन मौसम एवं पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2026 संकलन **(मिशन मौसम: 2,000 करोड़ रु.)**	**मिशन मौसम (2024–26)** द्वारा डॉप्लर रडार व कृत्रिम वर्षा/तड़ित नियंत्रण शोध; **पृथ्वी (4,797 करोड़ रु.)**	पीआईबी
100	अग्निपथ योजना एवं अदिति (अदिति / रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार)	रक्षा मंत्रालय	जून 2022 / 2026 संकलन	**4-वर्षीय अग्निवीर सेवा** (25% नियमित कैडर में; 11.71 लाख रु. सेवा निधि); **अदिति (750 करोड़ रु.)** में डिफेंस स्टार्टअप को 25 करोड़ रु. तक अनुदान	पीआईबी
101	वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी)	गृह मंत्रालय	फरवरी 2023 **(4,800 करोड़ रु.)**	उत्तरी सीमा के **4 राज्यों (अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड) और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश** के 19 ज़िलों के **2,967 सीमावर्ती गाँवों** का विकास	पीआईबी
102	स्वामित्व एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	पंचायती राज मंत्रालय	24 अप्रैल 2020 / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2022–26)	ग्रामीण आबादी क्षेत्र के ड्रोन संपत्ति कार्ड **(स्वामित्व)** एवं **2.78 लाख पंचायती राज संस्थाओं** का सशक्तिकरण **(राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान — 5,911 करोड़ रु.)**	पीआईबी
103	आकांक्षी ज़िला एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम	नीति आयोग	जनवरी 2018 (आकांक्षी जिला कार्यक्रम) / जनवरी 2023 (आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम)	**112 आकांक्षी ज़िलों** (49 संकेतक) और **500 आकांक्षी विकासखंडों** (39 संकेतक) का समग्र कायाकल्प	नीति आयोग
104	पीएम-डिवाइन (प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल) एवं उन्नति योजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल **(6,600 करोड़ रु.)** / उन्नति **(10,037 करोड़ रु.)**	पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढाँचे हेतु 100% केंद्रीय क्षेत्रक **प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल** और औद्योगिक निवेश हेतु **उन्नति 2024**	पीआईबी
105	मिशन लाइफ (मिशन लाइफ़ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)) एवं ग्रीन क्रेडिट	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अक्टूबर 2022 (केवड़िया) / अक्टूबर 2023	पर्यावरण के लिए जीवनशैली (पर्यावरण-हितैषी नागरिक) जन-आंदोलन और वृक्षारोपण व जल संरक्षण हेतु व्यापार योग्य **ग्रीन क्रेडिट**	पीआईबी

क्र.	योजना का नाम	नोडल केंद्रीय मंत्रालय	शुभारंभ / संशोधन वर्ष	मुख्य उद्देश्य, लक्षित वर्ग एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
106	मिष्टी (मिष्टी) एवं अमृत धरोहर योजना	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बजट 2025–26	**मिष्टी** द्वारा 9 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में **मैंग्रोव वनों** का संरक्षण; **अमृत धरोहर** द्वारा **रामसर आर्द्रभूमियों** का संरक्षण	पीआईबी
107	स्वदेश दर्शन 2.0 एवं प्रसाद (प्रसाद)	पर्यटन मंत्रालय	2025–26 में पुनर्गठित	टिकाऊ पर्यटन गंतव्यों का विकास (**स्वदेश दर्शन 2.0**) एवं तीर्थस्थलों का कायाकल्प (**प्रसाद**)	पीआईबी
108	खेलो इंडिया एवं कीर्ति (कीर्ति) कार्यक्रम	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	2017 / 2026 संकलन (कीर्ति)	**1,000+ खेलो इंडिया केंद्र**; **कीर्ति (कीर्ति)** द्वारा **9 से 18 वर्ष** के स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभाओं की पहचान	पीआईबी

क्या आप जानते हैं?: 2026 संकलन में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के अंतर्गत **2,000 करोड़ रुपये** के परिव्यय से **'मिशन मौसम' (मिशन मौसम)** को मंज़ूरी दी, जिसके तहत भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान), पुणे में **कृत्रिम बादल निर्माण/वर्षा वृद्धि और आकाशीय बिजली (तड़ित) नियंत्रण** के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **परीक्षा सावधानी बिंदु: पीएम-डिवाइन (प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल — 6,600 करोड़ रु.)** पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) द्वारा संचालित **100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना (केंद्रीय क्षेत्रक योजना)** है—इसे 90:10 अनुपात वाली केंद्र प्रायोजित योजना न समझें! (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

★ **स्मरण सूत्र: वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) के 4 राज्यों + 1 केंद्र शासित प्रदेश** को पश्चिम से पूर्व क्रम में **"ल-हि-उ-सि-अ" (ल-हि-उ-सि-अ)** से याद रखें: **ल**द्दाख (केंद्र शासित प्रदेश), **हि**माचल प्रदेश, **उ**त्तराखंड, **सि**क्किम और **अ**रुणाचल प्रदेश!

अध्याय 8: प्रमुख राज्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, राष्ट्रीय जन-अभियान एवं डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 8: प्रमुख राज्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, राष्ट्रीय जन-अभियान एवं डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
विभिन्न राज्यों की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं अन्य)	**प्रमुख राष्ट्रीय जन-अभियान एवं डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पोर्टल**	**राज्य कल्याणकारी योजनाएँ एवं डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)**	**भारत के सभी प्रमुख राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत सारणी (1 से 30)**

8.1 विभिन्न राज्यों की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं अन्य)

• **उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ:**

• **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना:** बालिका के जन्म से लेकर स्नातक/डिप्लोमा प्रवेश तक **6 चरणों में मिलने वाली कुल सहायता राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति बालिका** कर दिया गया है (पारिवारिक वार्षिक आय सीमा ≤ 3 लाख रुपये; अधिकतम 2 बालिकाएँ) (आईयूसी अकादमी)।

• **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान):** उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं (10 वर्षों में 10 लाख युवाओं) को **5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त और गारंटी-मुक्त ऋण** प्रदान किया जाता है।

• **एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) एवं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना:** 24 जनवरी 2018 (उत्तर प्रदेश दिवस) को प्रारंभ ओडीओपी प्रदेश के सभी 75 **ज़िलों** के विशिष्ट शिल्प/उत्पाद को वैश्विक बाज़ार देता है, जबकि युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उच्च शिक्षा के छात्रों को **2 करोड़ निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट** वितरित किए जा रहे हैं (आईयूसी अकादमी)।

• **मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं राजस्थान की प्रमुख योजनाएँ:**

• **मध्य प्रदेश — मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना एवं पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा:** पात्र महिलाओं (21–60 वर्ष) को **1,250 रुपये प्रतिमाह (15,000 रु./वर्ष)** डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं।

• **महाराष्ट्र — मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना एवं नमो शेतकरी महासन्मान निधि:** 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को **1,500 रुपये प्रतिमाह (18,000 रु./वर्ष)** दिए जाते हैं; **लेक लाडकी योजना** में बालिका को 18 वर्ष की आयु तक **1,01,000 रुपये** मिलते हैं; तथा **नमो शेतकरी महासन्मान निधि** में किसानों को पीएम-किसान के 6,000 रुपये के अतिरिक्त राज्य सरकार से **6,000 रुपये/वर्ष (कुल 12,000 रु./वर्ष)** मिलते हैं।

• **ओडिशा — सुभद्रा योजना (सुभद्रा योजना — 17 2026 संकलन को शुभारंभ):** 21 से 60 वर्ष की आयु की **1 करोड़ से अधिक महिलाओं** को **5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये** (रक्षाबंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर **5,000–5,000 रुपये की दो किस्तों में** — कुल **50,000 रुपये प्रति महिला**) तथा 'सुभद्रा डेबिट कार्ड' दिया जाता है (पीआईबी ओडिशा विज्ञप्ति नवंबर 2026)।

• **छत्तीसगढ़ — महतारी वंदना योजना:** 21 वर्ष और उससे अधिक आयु की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को **1,000 रुपये प्रतिमाह (12,000 रु./वर्ष)**।

• **बिहार — सात निश्चय-2, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना:** स्नातक उत्तीर्ण करने पर अविवाहित/विवाहित छात्राओं को **50,000 रुपये** (तथा इंटरमीडिएट अविवाहित उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये) की प्रोत्साहन राशि, और युवा/महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग उद्यमियों को **10 लाख रुपये (5 लाख रु. अनुदान + 5 लाख रु. ऋण)** (आईयूसी अकादमी)।

• **राजस्थान — लाडो प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (माँ) योजना:** बालिका के जन्म व शिक्षा पर 7 चरणों में **1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड** तथा प्रत्येक परिवार को **25 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा**।

8.2 प्रमुख राष्ट्रीय जन-अभियान एवं डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पोर्टल

• **'एक पेड़ माँ के नाम' (माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान):** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा **5 2026 संकलन (विश्व पर्यावरण दिवस)** को नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत देश भर में **100 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य** निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **प्रमुख डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल एवं ऐप्स (1 से 30):**

क्र.	पोर्टल / मोबाइल ऐप का नाम	संबंधित मंत्रालय / संस्था	मुख्य कार्य एवं नागरिक उपयोगिता	आधिकारिक स्रोत
1	पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल	शिक्षा मंत्रालय	860 शीर्ष शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित छात्रों को बिना गारंटी शिक्षा ऋण व 3% ब्याज छूट हेतु एकल खिड़की पोर्टल	पीआईबी
2	यू-विन (यू-विन) पोर्टल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	गर्भवती महिलाओं और बच्चों के 12 टीकों का इलेक्ट्रॉनिक टीकाकरण रजिस्टर	पीआईबी
3	पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	रूफशीर्ष सोलर आवेदन, वेंडर चयन, नेट-मीटरिंग और 78,000 रु. तक सब्सिडी भुगतान का ऑनलाइन पोर्टल	पीआईबी
4	साथी (साथी) पोर्टल	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	बीज प्रमाणन, पता लगाने की क्षमता एवं समग्र इन्वेंट्री — क्यूआर कोड द्वारा प्रमाणित बीज ट्रेसबिलिटी	पीआईबी
5	सारथी पोर्टल एवं कृषि रक्षक (14447)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	फसल बीमा व ग्रामीण संपत्तियों का बीमा पोर्टल तथा किसानों के लिए 14447 टोल-फ्री शिकायत हेल्पलाइन	पीआईबी
6	विंड्स (विंड्स) पोर्टल	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशनों से सटीक मौसम डेटा संकलन	पीआईबी
7	भू-नीर (भू-नीर) पोर्टल	जल शक्ति मंत्रालय (केंद्रीय भूमि जल बोर्ड)	2026 संकलन में शुभारंभ; देश भर में भूजल निकासी की अनुमति (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) और नियमन हेतु केंद्रीकृत पोर्टल	पीआईबी
8	फ्लडवॉच इंडिया 2.0 ऐप	जल शक्ति मंत्रालय (केंद्रीय जल आयोग)	592 निगरानी स्टेशनों से वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति और 7 दिनों का बाढ़ पूर्वानुमान	पीआईबी
9	ई-श्रम वन-स्शीर्ष सॉल्यूशन	श्रम और रोज़गार मंत्रालय	30 करोड़+ असंगठित श्रमिकों के लिए 12+ केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का एकीकृत मंच	पीआईबी

क्र.	पोर्टल / मोबाइल ऐप का नाम	संबंधित मंत्रालय / संस्था	मुख्य कार्य एवं नागरिक उपयोगिता	आधिकारिक स्रोत
10	स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच)	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	कौशल प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रमाणन, अप्रेंटिसशिप और रोज़गार अवसरों का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	पीआईबी
11	नीति फॉर स्टेट्स (राज्यों के लिए नीति मंच)	नीति आयोग	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7,500+ सर्वोत्तम प्रथाओं व नीतिगत डेटा का डिजिटल कोष	नीति आयोग
12	मेरी पंचायत ऐप एवं ग्राम मानचित्र	पंचायती राज मंत्रालय	2.65 लाख ग्राम पंचायतों के बजट व विकास योजनाओं की निगरानी (**मेरी पंचायत**) एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थानिक नियोजन (**ग्राम मानचित्र**)	पीआईबी
13	पोषण ट्रैकर ऐप एवं शी-बॉक्स (शी-बॉक्स)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की रियल-टाइम निगरानी (**पोषण ट्रैकर**) एवं कार्यस्थल यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण पोर्टल (**शी-बॉक्स**)	पीआईबी
14	ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति एवं ई-समन ऐप	गृह मंत्रालय / न्याय विभाग	नए आपराधिक कानूनों (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) के तहत अपराध स्थल की वीडियोग्राफी (**ई-साक्ष्य**), वर्चुअल गवाही (**न्याय श्रुति**) व इलेक्ट्रॉनिक समन	पीआईबी
15	चक्षु (चक्षु) पोर्टल (संचार साथी)	दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग)	संदिग्ध स्पैम/धोखाधड़ी वाले कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों की नागरिकों द्वारा रिपोर्टिंग का पोर्टल	पीआईबी
16	अपार आईडी (अपार पहचान पत्र) एवं स्वयं प्लस	शिक्षा मंत्रालय	एक राष्ट्र एक छात्र पहचान पत्र — 12-अंकीय आजीवन शैक्षणिक क्रेडिट आईडी (**अपार**) एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम (**स्वयं प्लस**)	पीआईबी
17	प्रेरणा (प्रेरणा) पोर्टल	शिक्षा मंत्रालय	कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए **वडनगर (गुजरात)** के ऐतिहासिक स्कूल में अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम	पीआईबी
18	सी-केयर्स (सी-केयर्स) एवं स्वाति (स्वाति)	कोयला मंत्रालय / प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार	कोयला खदान भविष्य निधि का डिजिटलीकरण (**सी-केयर्स**) तथा विज्ञान व गणित (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित एवं चिकित्सा) में भारतीय महिलाओं का पोर्टल (**स्वाति**)	पीआईबी
19	अन्न चक्र एवं ई-जागृति पोर्टल	खाद्य एवं उपभोक्ता कार्य मंत्रालय	पीडीएस खाद्यान्न आपूर्ति मार्ग अनुकूलन (**अन्न चक्र**) तथा उपभोक्ता आयोगों में ऑनलाइन वाद दायर करने का एआई पोर्टल (**ई-जागृति**)	पीआईबी
20	भाषिणी (भाषिणी) एवं विद्यार्थी केंद्र	इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय एवं आईयूसी अकादमी	संविधान की 22 **अनुसूचित भाषाओं** में एआई अनुवाद (**भाषिणी**) एवं मुफ़्त सरकारी परीक्षा मॉक टेस्ट व समसामयिकी हब (**विद्यार्थी केंद्र**)	आईयूसी अकादमी

8.3 राज्य कल्याणकारी योजनाएँ एवं डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रवाह आरेख (चार-चरणीय प्रवाह आरेख)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: राज्यों की महिला डीबीटी योजनाएँ (उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला 25 हज़ार, ओडिशा सुभद्रा 50 हज़ार, मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र)

चरण 2
चरण 2: युवा उद्यमिता प्रोत्साहन (उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 5 लाख रु. ब्याज-मुक्त व बिहार उद्यमी 10 लाख रु.)

चरण 3
चरण 3: राष्ट्रीय जन-आंदोलन ('एक पेड़ माँ के नाम' 100 करोड़+ वृक्ष व जनजातीय गौरव दिवस)

चरण 4
चरण 4: आधार, यूपीआई, भाषिणी (22 भाषाएँ), ओएनडीसी, जेम एवं सीपीग्राम्स से पारदर्शी वितरण]`

क्या आप जानते हैं?: केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (**सीपीग्राम्स** — प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित) में नागरिकों की शिकायतों के निवारण की अधिकतम समय-सीमा को 30 दिनों से घटाकर **21 दिन** कर दिया गया है और इसे **भाषिणी (22 भारतीय भाषाओं)** के साथ जोड़ा गया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा सावधानी बिंदु: ओडिशा की सुभद्रा योजना (प्रतिवर्ष 10,000 रु. = 5,000 रु. की 2 किस्तें, 5 वर्षों में कुल 50,000 रु.), छत्तीसगढ़ की महतारी वंदना योजना (1,000 रु./माह = 12,000 रु./वर्ष), मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना (1,250 रु./माह) और **महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहीण योजना (1,500 रु./माह)** की राशि में अंतर अवश्य याद रखें (पीआईबी नवंबर 2026)।

★ **स्मरण सूत्र:** राज्यों की महिला डीबीटी योजनाओं की राशि को **"1,000 (छत्तीसगढ़/तमिलनाडु) – 1,250 (मध्य प्रदेश/असम) – 1,500 (महाराष्ट्र) – 2,000 (कर्नाटक) – 5,000दोगुना (ओडिशा सुभद्रा)"** के आरोही क्रम से याद रखें!

8.4 भारत के सभी प्रमुख राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत सारणी (1 से 30)

क्र.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	प्रमुख राज्य योजना / अभियान का नाम	लक्षित लाभार्थी वर्ग	मुख्य वित्तीय प्रावधान एवं परीक्षोपयोगी तथ्य	आधिकारिक स्रोत
1	उत्तर प्रदेश	मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, युवा उद्यमी विकास अभियान एवं एक ज़िला एक उत्पाद	बालिकाएँ (जन्म से स्नातक), युवा उद्यमी एवं 75 ज़िलों के शिल्पकार	बालिका को 6 चरणों में **25,000 रु.**; प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को **5 लाख रु. ब्याज-मुक्त ऋण**; 2 करोड़ मुफ़्त स्मार्टफोन/टैबलेट	आईयूसी अकादमी
2	मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी 2.0 एवं पीएम श्री एयर एम्बुलेंस	महिलाएँ (21–60 वर्ष), बालिकाएँ एवं आयुष्मान कार्डधारक	पात्र महिलाओं को **1,250 रु./माह (15,000 रु./वर्ष)** डीबीटी; गंभीर रोगियों हेतु निःशुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा	आईयूसी अकादमी
3	बिहार	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सात निश्चय-2 एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना	स्नातक छात्राएँ एवं युवा/महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग उद्यमी	स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को **50,000 रु.**; नए उद्यम हेतु **10 लाख रु. (5 लाख रु. अनुदान + 5 लाख रु. ऋण)**	आईयूसी अकादमी
4	राजस्थान	लाडो प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना	बालिकाएँ एवं राज्य के सभी परिवार	बालिका के जन्म व शिक्षा पर 7 चरणों में **1,00,000 रु. का सेविंग बॉन्ड**; प्रति परिवार **25 लाख रु.** का स्वास्थ्य बीमा	आईयूसी अकादमी
5	महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, लेक लाडकी एवं नमो शेतकरी महासन्मान निधि	महिलाएँ (21–65 वर्ष), बालिकाएँ एवं किसान	महिलाओं को **1,500 रु./माह**; लेक लाडकी में **1,01,000 रु.**; किसानों को राज्य से **6,000 रु./वर्ष अतिरिक्त** (कुल 12,000 रु.)	आईयूसी अकादमी
6	ओडिशा	सुभद्रा योजना एवं सीएम-किसान (कृषक कल्याण योजना)	महिलाएँ (21–60 वर्ष) एवं लघु/सीमांत/भूमिहीन किसान	1 करोड़+ महिलाओं को 5 वर्षों तक **10,000 रु./वर्ष (5,000 रु. की 2 किस्तें = कुल 50,000 रु.)**; किसानों को 4,000 रु./वर्ष	पीआईबी नवंबर 2026
7	छत्तीसगढ़	महतारी वंदना योजना एवं कृषक उन्नति योजना	विवाहित/विधवा महिलाएँ (≥21 वर्ष) एवं धान उत्पादक किसान	70 लाख+ महिलाओं को **1,000 रु./माह (12,000 रु./वर्ष)**; **3,100 रु./क्विंटल** की दर से धान खरीद (21 क्विंटल/एकड़ तक)	आईयूसी अकादमी
8	झारखंड	मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना एवं अबुआ आवास योजना	महिलाएँ (18–50 वर्ष) एवं आवासहीन ग्रामीण परिवार	महिलाओं को मासिक सम्मान राशि; **अबुआ आवास योजना** में **3 कमरों के पक्के मकान हेतु 2,00,000 रुपये**	आईयूसी अकादमी
9	असम	ओरुनोदोई 3.0 एवं मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना	आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार एवं छात्राएँ (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर)	37.2 लाख परिवारों की महिलाओं को **1,250 रु./माह**; बाल विवाह रोकने हेतु छात्राओं को **1,000 से 2,500 रु./माह** वज़ीफ़ा	आईयूसी अकादमी
10	पश्चिम बंगाल	लक्ष्मी भंडार योजना (2026 संकलन में संवर्धित) एवं कन्याश्री प्रकल्प	महिलाएँ (25–60 वर्ष) एवं किशोरियाँ (13–19 वर्ष)	2024 से **अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं को 1,200 रु./माह** तथा **सामान्य/ओबीसी महिलाओं को 1,000 रु./माह**; संयुक्त राष्ट्र पुरस्कृत **कन्याश्री**	आईयूसी अकादमी
11	कर्नाटक	पंच गारंटी योजनाएँ (गृह लक्ष्मी, शक्ति, अन्न भाग्य, गृह ज्योति, युवा निधि)	महिला मुखिया, यात्री, एनएफएसए परिवार, बिजली उपभोक्ता एवं बेरोज़गार स्नातक	**2,000 रु./माह** (गृह लक्ष्मी), मुफ़्त बस यात्रा (शक्ति), **200 यूनिट मुफ़्त बिजली** (गृह ज्योति), **3,000/1,500 रु.** (युवा निधि)	आईयूसी अकादमी
12	तेलंगाना	महालक्ष्मी योजना, रायथु भरोसा, गृह ज्योति एवं इंदिरम्मा इंदलु	महिलाएँ, किसान एवं आवासहीन परिवार	महिलाओं को **2,500 रु./माह** + मुफ़्त बस यात्रा + 500 रु. गैस सिलेंडर; किसानों को **15,000 रु./एकड़**; आवास हेतु **5 लाख रु.**	आईयूसी अकादमी
13	तमिलनाडु	कलैगनार मगलिर उरिमई, पुधुमई पेन, तमिल पुधलवन एवं मुख्यमंत्री नाश्ता योजना	महिला परिवार मुखिया, सरकारी स्कूल के छात्र/छात्राएँ एवं प्राथमिक बच्चे	1.15 करोड़ महिलाओं को **1,000 रु./माह**; उच्च शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्र व छात्राओं को **1,000 रु./माह**; स्कूलों में सुबह का नाश्ता	आईयूसी अकादमी
14	आंध्र प्रदेश	तल्लिकी वंदनम एवं अन्नदाता सुखीभव योजना	स्कूली बच्चों की माताएँ एवं किसान परिवार	प्रत्येक स्कूली बच्चे के लिए माँ के खाते में **15,000 रु./वर्ष**; किसानों को कुल **20,000 रु./वर्ष** (पीएम-किसान सहित)	आईयूसी अकादमी
15	गुजरात	नमो लक्ष्मी योजना एवं नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना	माध्यमिक छात्राएँ (कक्षा 9–12) एवं विज्ञान वर्ग के छात्र (कक्षा 11–12)	कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को 4 वर्षों में **50,000 रु.**; कक्षा 11–12 में विज्ञान पढ़ने पर **25,000 रु.** की छात्रवृत्ति	आईयूसी अकादमी

क्र.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	प्रमुख राज्य योजना / अभियान का नाम	लक्षित लाभार्थी वर्ग	मुख्य वित्तीय प्रावधान एवं परीक्षोपयोगी तथ्य	आधिकारिक स्रोत
16	हरियाणा	लाडो लक्ष्मी योजना एवं चिरायु हरियाणा (आयुष्मान विस्तार)	महिलाएँ एवं 1.80 लाख रु. तक वार्षिक आय वाले परिवार	महिलाओं को मासिक डीबीटी सहायता; 1.80 लाख रु. तक आय वाले परिवारों को **5 लाख रु. तक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा**	आईयूसी अकादमी
17	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना	महिलाएँ (18–59 वर्ष) एवं अनाथ बच्चे	पात्र महिलाओं को **1,500 रु./माह**; अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक कानूनी रूप से **'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट'** का दर्जा	आईयूसी अकादमी
18	उत्तराखंड	मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना एवं मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव	ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह एवं महिला शिल्पकार	1.25 लाख+ एसएचजी महिलाओं को 5 लाख रु. तक के ब्याज-मुक्त ऋण द्वारा लखपति बनाना व स्थानीय उत्पादों का विपणन	आईयूसी अकादमी
19	पंजाब	भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार एवं आम आदमी क्लीनिक	समस्त नागरिक एवं बाह्य रोगी (बाह्य रोगी विभाग)	हेल्पलाइन **1076** के माध्यम से **43+ नागरिक सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी**; 800+ मोहल्ला क्लीनिक में मुफ़्त जांच व दवाएँ	आईयूसी अकादमी
20	केरल	कुटुंबश्री मिशन एवं अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना	महिला स्वयं सहायता नेटवर्क एवं अत्यंत निर्धन परिवार	**46 लाख+ महिलाओं** का विश्व का सबसे बड़ा सामुदायिक नेटवर्क; सूक्ष्म योजनाओं द्वारा अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन	आईयूसी अकादमी
21	गोवा	गृह आधार योजना एवं लाडली लक्ष्मी योजना	गृहिणियाँ एवं युवा बालिकाएँ	मुद्रास्फीति से राहत हेतु गृहिणियों को **1,500 रु./माह**; बालिकाओं के विवाह/उच्च शिक्षा हेतु **1,00,000 रु.** की सहायता	आईयूसी अकादमी
22	सिक्किम	मेरो रुख मेरो संतति एवं आमा (आमा) / बहिनी योजना	नवजात शिशु, गैर-कामकाजी माताएँ एवं स्कूली छात्राएँ	प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म पर **100 पेड़ लगाना (मेरो रुख मेरो संतति)**; माताओं को **20,000 रु./वर्ष (आमा योजना)**	आईयूसी अकादमी
23	अरुणाचल प्रदेश	आत्मनिर्भर कृषि / बागवानी योजना एवं दुलारी कन्या योजना	किसान, स्वयं सहायता समूह एवं नवजात बालिकाएँ	कृषि/बागवानी ऋण पर **45% अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी**; संस्थागत प्रसव से जन्मी बालिका के नाम **20,000 रु. की सावधि जमा**	आईयूसी अकादमी
24	मेघालय	सीएम-एलिवेट (मुख्यमंत्री एलिवेट) एवं केंद्रित (फोकस+) कार्यक्रम	युवा उद्यमी एवं किसान उत्पादक समूह	युवा व्यवसाय हेतु **35% से 75% पूंजीगत सब्सिडी**; किसान उत्पादक समूहों के प्रत्येक सदस्य को **5,000 रु.** की सहायता	आईयूसी अकादमी
25	मिज़ोरम	बाना काइह (बाना काईह — हैंडहोल्डिंग) नीति	किसान एवं सूक्ष्म उद्यमी	समय पर ऋण चुकाने वाले उद्यमियों को **50 लाख रु. तक के बिना गारंटी ऋण पर 100% ब्याज छूट** व प्रमुख फसलों की खरीद	आईयूसी अकादमी
26	त्रिपुरा	मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना एवं चा सुंदरी योजना	मेधावी छात्राएँ एवं चाय बागान श्रमिक	कक्षा 12 बोर्ड की शीर्ष 140+ छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी; चाय बागान श्रमिकों को आवास व सामाजिक सुरक्षा	आईयूसी अकादमी
27	मणिपुर एवं नागालैंड	मुख्यमंत्री हकशेलगी तेंगबांग (मणिपुर) एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा (नागालैंड)	कम आय वाले परिवार एवं मूल निवासी	मणिपुर में 5 लाख रु. तक और नागालैंड (मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना) में **5 लाख रु. से 20 लाख रु. तक** का कैशलेस स्वास्थ्य उपचार	आईयूसी अकादमी
28	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख	मिशन युवा (जम्मू-कश्मीर) एवं कार्बन-न्यूट्रल हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी (लद्दाख)	युवा उद्यमी एवं उच्च-ऊंचाई वाले परिवार	जम्मू-कश्मीर में **1.37 लाख नए उद्यम व 4.25 लाख रोज़गार (मिशन युवा)**; लेह में भारत की प्रथम हरित हाइड्रोजन बस सेवा	पीआईबी

हल सहित परीक्षा अभ्यास प्रश्न (45 उच्च-स्तरीय चार-विकल्पीय अभ्यास प्रश्न)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न: पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये) के अंतर्गत 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के आवासीय रूफशीर्ष सोलर प्लांट पर क्रमशः कितनी प्रत्यक्ष सब्सिडी (सीएफए) दी जाती है?**
(क) 20,000 रु. (1 किलोवाट), 40,000 रु. (2 किलोवाट) और 60,000 रु. (3 किलोवाट+)
(ख) 30,000 रु. (1 किलोवाट), 60,000 रु. (2 किलोवाट) और 78,000 रु. (3 किलोवाट एवं उससे अधिक पर अधिकतम सीमा)
(ग) 30,000 रु. (1 किलोवाट), 60,000 रु. (2 किलोवाट) और 90,000 रु. (3 किलोवाट+)
(घ) 25,000 रु. (1 किलोवाट), 50,000 रु. (2 किलोवाट) और 75,000 रु. (3 किलोवाट+)
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट पर 30,000 रु., 2 किलोवाट पर 60,000 रु. और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर अधिकतम 78,000 रु. की सब्सिडी दी जाती है (पीआईबी पीएम सूर्य घर विवरण)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न: पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के तहत वित्त वर्ष 2026–27 तक कितने घरों में रूफशीर्ष सोलर लगाने और प्रति परिवार प्रतिमाह कितनी यूनिट तक मुफ़्त बिजली देने का लक्ष्य है?**
(क) 50 लाख घर; 200 यूनिट/माह
(ख) 1 करोड़ घर; प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली
(ग) 2 करोड़ घर; 300 यूनिट/माह
(घ) 1.5 करोड़ घर; 250 यूनिट/माह
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** 2026 संकलन में 75,021 करोड़ रु. के परिव्यय से शुरू इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली देना है (पीआईबी पीएम सूर्य घर 2026)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न: भारत के 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये) के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष कितने मिलियन मीस्मरण सूत्र टन (एमएमटी) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है?**
(क) 2 मिलियन मीस्मरण सूत्र टन (एमएमटी) प्रतिवर्ष
(ख) 5 मिलियन मीस्मरण सूत्र टन (एमएमटी) प्रतिवर्ष (125 गीगावाट संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा के साथ)
(ग) 10 मिलियन मीस्मरण सूत्र टन (एमएमटी) प्रतिवर्ष
(घ) 15 मिलियन मीस्मरण सूत्र टन (एमएमटी) प्रतिवर्ष
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (19,744 करोड़ रु.) का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन उत्पादन और 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न: 2026 संकलन में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा फेम-द्वितीय के स्थान पर इलेक्स्मरण सूत्र वाहनों (ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक व 14,028 ई-बस) को प्रोत्साहित करने के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से कौन-सी नई योजना शुरू की गई?**
(क) पीएम-ईबस सेवा
(ख) पीएम ई-ड्राइव योजना (पीएम ई-ड्राइव योजना)
(ग) नेशनल इलेक्स्मरण सूत्र मोबिलिटी मिशन 2.0
(घ) हरित वाहन योजना
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** 2026 संकलन में 10,900 करोड़ रु. के परिव्यय से पीएम ई-ड्राइव (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव) योजना को मंज़ूरी दी गई (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) के 2024–29 विस्तार (परिव्यय 3,06,137 करोड़ रुपये) के तहत कितने अतिरिक्त ग्रामीण घर बनाए जा रहे हैं और मैदानी बनाम पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में इकाई सहायता कितनी है?**
(क) 1 करोड़ घर; मैदानी 1.00 लाख रु. व पहाड़ी 1.20 लाख रु.
(ख) 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घर; मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रु. तथा हिमालयी/पूर्वोत्तर राज्यों व जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में 1.30 लाख रु.
(ग) 3 करोड़ घर; सभी जगह 1.50 लाख रु.
(घ) 1.5 करोड़ घर; 1.20 लाख रु. व 1.50 लाख रु.
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (2024–29) के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रु. और पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 1.30 लाख रु. दिए जाते हैं (पीआईबी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विज्ञप्ति)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न: 29 2026 संकलन को शुरू की गई 'आयुष्मान वय वंदना' पहल के अंतर्गत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु और आय पात्रता क्या है?**
(क) 60 वर्ष और अधिक आयु तथा वार्षिक आय 5 लाख रु. से कम
(ख) 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक — चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति या आय कुछ भी हो (कोई आय सीमा नहीं)
(ग) केवल बीपीएल परिवारों के 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग
(घ) केवल गैर-आयकरदाता 70+ वर्ष के नागरिक
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** आयुष्मान वय वंदना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक बिना किसी आय सीमा के 5 लाख रु. के स्वास्थ्य कवर के पात्र हैं (पीआईबी आयुष्मान वय वंदना 2026)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

7. **प्रश्न: यदि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई वरिष्ठ नागरिक पहले से ही आयुष्मान भारत पीएम-जय के तहत कवर किए गए परिवार से संबंधित है, तो उसे 'आयुष्मान वय वंदना' के तहत कितना अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर मिलता है?**
(क) 2.5 लाख रुपये का साझा कवर
(ख) स्वयं के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त अनन्य अतिरिक्त कवर (जिससे परिवार का कुल कवर 10 लाख रु. हो जाता है)
(ग) कोई अतिरिक्त कवर नहीं; मौजूदा 5 लाख रु. ही साझा करना होगा
(घ) 3 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** मौजूदा एबी पीएम-जय परिवारों के 70+ वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनन्य अतिरिक्त कवर मिलता है (पीआईबी आयुष्मान वय वंदना 2026)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

8. **प्रश्न: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविन की तर्ज पर प्रत्येक गर्भवती महिला और बच्चे के 12 टीकों का डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड रखने के लिए कौन-सा राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया है?**
(क) ई-संजीवनी (ई-संजीवनी)
(ख) यू-विन पोर्टल (यू-विन पोर्टल)
(ग) पोषण ट्रैकर
(घ) निक्षय 2.0
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** यू-विन (यू-विन) पोर्टल गर्भवती महिलाओं और बच्चों के सार्वभौमिक टीकाकरण की डिजिटल ट्रैकिंग करता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

9. **प्रश्न: शहडोल (मध्य प्रदेश) से शुरू किए गए 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन' के तहत भारत से सिकल सेल रोग को किस वर्ष तक समाप्त करने और कितने लोगों की जांच करने का लक्ष्य है?**
(क) वर्ष 2030 तक; 3 करोड़ लोगों की जांच
(ख) वर्ष 2047 तक; 17 राज्यों के 278 जनजातीय ज़िलों में 0–40 वर्ष के 7 करोड़ लोगों की जांच
(ग) वर्ष 2035 तक; 5 करोड़ लोगों की जांच
(घ) वर्ष 2028 तक; 2 करोड़ लोगों की जांच
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** 1 जुलाई 2023 को शहडोल (मध्य प्रदेश) से शुरू इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन हेतु 7 करोड़ लोगों की जांच करना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

10. **प्रश्न: संशोधित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0) के अंतर्गत प्रथम जीवित संतान पर और दूसरी संतान बालिका (लड़की) होने पर क्रमशः कितनी मातृत्व सहायता राशि दी जाती है?**
(क) प्रथम संतान पर 3,000 रु. और दूसरी बालिका पर 5,000 रु.
(ख) प्रथम संतान पर 5,000 रु. (2 किस्तों में) और दूसरी संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6,000 रु.
(ग) सभी संतानों पर समान 6,000 रु.
(घ) प्रथम संतान पर 5,000 रु. और दूसरी बालिका पर 10,000 रु.
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएमएमवीवाई 2.0 के तहत प्रथम संतान पर 5,000 रु. और दूसरी संतान बालिका होने पर 6,000 रु. दिए जाते हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

11. **प्रश्न: जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का मानक निर्धारित है?**
(क) 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
(ख) 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)
(ग) 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
(घ) 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) शुद्ध नल जल उपलब्ध कराया जाता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

12. **प्रश्न: ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) की 'लखपति दीदी' पहल का संशोधित राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है और 'लखपति दीदी' किसे परिभाषित किया गया है?**
(क) 1 करोड़ महिलाएँ जिनकी जीवनकाल आय 1 लाख रु. हो
(ख) 3 करोड़ एसएचजी महिलाएँ (2 करोड़ से बढ़ाकर) जिनकी वार्षिक शुद्ध पारिवारिक आय कम से कम 1,00,000 रुपये या अधिक हो
(ग) 5 करोड़ शहरी महिलाएँ
(घ) 2 करोड़ महिला किसान
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** लखपति दीदी पहल का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ एसएचजी महिलाएँ किया गया है, जिनकी वार्षिक शुद्ध आय ≥ 1,00,000 रु. हो (पीआईबी लखपति दीदी नवंबर 2026)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

13. **प्रश्न: नमो ड्रोन दीदी योजना (परिव्यय 1,261 करोड़ रुपये, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) के तहत कितने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि ड्रोन दिए जा रहे हैं और इस पर सब्सिडी की दर व अधिकतम सीमा क्या है?**
(क) 10,000 एसएचजी; 50% सब्सिडी (अधिकतम 5 लाख रु.)
(ख) 15,000 चयनित महिला एसएचजी; ड्रोन लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपये तक की सब्सिडी
(ग) 25,000 एसएचजी; 75% सब्सिडी (अधिकतम 7.5 लाख रु.)
(घ) 5,000 एसएचजी; 100% अनुदान
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** नमो ड्रोन दीदी योजना में 15,000 महिला एसएचजी को ड्रोन लागत पर 80% (अधिकतम 8 लाख रु.) की सब्सिडी दी जाती है (पीआईबी विकसित भारत विज्ञप्ति)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

14. **प्रश्न: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 'मिशन शक्ति' के दो उप-घटक कौन-से हैं, और वन स्शीर्ष सेंटर (वन स्टॉप सेंटर), महिला हेल्पलाइन (181), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा 'नारी अदालत' किस उप-घटक में शामिल हैं?**
(क) पोषण और वात्सल्य; पोषण में शामिल
(ख) 'संबल' (सुरक्षा) और 'सामर्थ्य' (सशक्तिकरण); वन स्टॉप सेंटर, 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व नारी अदालत 'संबल' में शामिल हैं
(ग) शक्ति सदन और सखी निवास
(घ) उज्ज्वला और स्वाधार
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** मिशन शक्ति के दो उप-घटक 'संबल' (वन स्टॉप सेंटर, 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत) और 'सामर्थ्य' (पीएमएमवीवाई, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास) हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

15. **प्रश्न: डॉ. टी.वी. सोमनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित 'एकीकृत पेंशन योजना' (एकीकृत पेंशन योजना — यूपीएस) कब से प्रभावी हुई और पूर्ण 50% सुनिश्चित पेंशन के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की अर्हक सेवा आवश्यक है?**
(क) 1 जनवरी 2025; न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा
(ख) 1 अप्रैल 2025; न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा (अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%)
(ग) 1 जुलाई 2025; न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा
(घ) 2 2026 संकलन; न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** डॉ. टी.वी. सोमनाथन समिति की सिफारिश पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई, जिसमें 25 वर्ष की सेवा पर अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन सुनिश्चित है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

16. **प्रश्न: एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की दर, 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, और केंद्र सरकार के अंशदान की नई दर क्रमशः क्या है?**
(क) 50% पारिवारिक पेंशन; 8,000 रु. न्यूनतम पेंशन; 14% सरकारी अंशदान
(ख) पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन; 10,000 रु./माह न्यूनतम पेंशन (≥10 वर्ष सेवा); 18.5% सरकारी अंशदान (कर्मचारी अंशदान 10%)
(ग) 60% पारिवारिक पेंशन; 12,000 रु. न्यूनतम; 20% सरकारी अंशदान
(घ) 40% पारिवारिक पेंशन; 9,000 रु. न्यूनतम; 16.5% सरकारी अंशदान
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** यूपीएस में 60% पारिवारिक पेंशन, 10+ वर्ष सेवा पर 10,000 रु./माह न्यूनतम पेंशन और 18.5% सरकारी अंशदान का प्रावधान है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

17. **प्रश्न: 18 2026 संकलन को शुरू की गई 'एनपीएस वात्सल्य योजना' के लिए कौन पात्र हैं, इसमें न्यूनतम वार्षिक अंशदान कितना है और लाभार्थी के 18 वर्ष का होने पर क्या होता है?**
(क) केवल 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाएँ; 250 रु./वर्ष
(ख) 0 से 18 वर्ष आयु के सभी नाबालिग नागरिक; न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिवर्ष (अधिकतम की कोई सीमा नहीं); 18 वर्ष होने पर नियमित एनपीएस प्रथम श्रेणी खाते में स्वतः रूपांतरण
(ग) 5 से 18 वर्ष के बच्चे; न्यूनतम 500 रु./माह
(घ) केवल अनाथ बच्चे; सरकार द्वारा 10 लाख रु. जमा
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** एनपीएस वात्सल्य (18 2026 संकलन) में 0–18 वर्ष के सभी नाबालिगों के लिए न्यूनतम 1,000 रु./वर्ष से खाता खुलता है जो 18 वर्ष पर नियमित एनपीएस प्रथम श्रेणी में बदल जाता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

18. **प्रश्न: पीएम विश्वकर्मा योजना (17 सितंबर 2023 को शुभारंभ, परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये) में कितने पारंपरिक शिल्प/व्यवसाय शामिल हैं और इसमें टूलकिट प्रोत्साहन व उद्यम ऋण की शर्तें क्या हैं?**
(क) 12 व्यवसाय; 10,000 रु. टूलकिट; 7% ब्याज पर 2 लाख रु. ऋण
(ख) 18 पारंपरिक व्यवसाय; 15,000 रु. का टूलकिट ई-वाउचर; 5% रियायती ब्याज पर बिना गारंटी 3 लाख रु. तक का ऋण (1 लाख + 2 लाख रु.)
(ग) 24 व्यवसाय; 20,000 रु. टूलकिट; 5 लाख रु. ऋण
(घ) 15 व्यवसाय; 5,000 रु. टूलकिट; 1 लाख रु. ऋण
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएम विश्वकर्मा (13,000 करोड़ रु.) में 18 पारंपरिक शिल्पों को 15,000 रु. टूलकिट ई-वाउचर और 5% ब्याज पर 3 लाख रु. (1 लाख+2 लाख) ऋण मिलता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

19. **प्रश्न: 15 नवंबर 2023 (जनजातीय गौरव दिवस) को झारखंड के खूँटी से 24,104 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को 9 मंत्रालयों की 11 सुविधाओं से संतृप्त करने हेतु कौन-सी योजना शुरू की गई?**
(क) वनबंधु कल्याण योजना
(ख) पीएम-जनमन (पीएम-जनमन — प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान)
(ग) पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)
(घ) एकलव्य मिशन
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** 15 नवंबर 2023 को खूँटी (झारखंड) से 24,104 करोड़ रु. के परिव्यय से 75 पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन शुरू की गई (पीआईबी पीएम-जनमन जुलाई 2026)।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

20. **प्रश्न: 2 2026 संकलन को झारखंड के हज़ारीबाग से शुरू किए गए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान' (डीएजेजीयूए / प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान) का कुल परिव्यय और ग्राम कवरेज लक्ष्य क्या है?**
(क) 24,104 करोड़ रुपये; 15,000 पीवीटीजी बस्तियाँ
(ख) 79,156 करोड़ रुपये; 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के 63,843 जनजातीय-बहुल गाँव (5+ करोड़ जनजातीय आबादी को 17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेपों का लाभ)
(ग) 50,000 करोड़ रुपये; 25,000 गाँव
(घ) 13,000 करोड़ रुपये; 10,000 गाँव
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** 2 2026 संकलन को हज़ारीबाग से 79,156 करोड़ रु. के परिव्यय से धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू हुआ जो 63,843 गाँवों और 5+ करोड़ जनजातीय नागरिकों को कवर करता है (पीआईबी नवंबर 2026)।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

21. **प्रश्न: बजट 2024–25 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत पूर्व में 'तरुण' ऋण को सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमियों के लिए शुरू की गई नई 'तरुण प्लस' (तरुण प्लस) श्रेणी में ऋण की अधिकतम सीमा क्या है?**
(क) 15 लाख रुपये
(ख) 20 लाख रुपये (10 लाख रुपये की तरुण सीमा से दोगुनी)
(ग) 25 लाख रुपये
(घ) 50 लाख रुपये
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएम मुद्रा योजना की नई 'तरुण प्लस' श्रेणी में ऋण सीमा को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दिया गया है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

22. **प्रश्न: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (6 2026 संकलन को स्वीकृत, परिव्यय 3,600 करोड़ रुपये) में देश के कितने शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान (क्यूएचईआई) शामिल हैं तथा क्रेडिट गारंटी व ब्याज सब्सिडी का नियम क्या है?**
(क) शीर्ष 500 कॉलेज; 5 लाख रु. तक 50% गारंटी
(ख) शीर्ष 860 क्यूएचईआई; 7.5 लाख रु. तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी, तथा ≤ 8 लाख रु. पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रु. तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी
(ग) केवल शीर्ष 100 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान; सभी को 100% ब्याज छूट
(घ) सभी 40,000 कॉलेज; 2 लाख रु. छात्रवृत्ति
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएम विद्यालक्ष्मी (3,600 करोड़ रु.) शीर्ष 860 क्यूएचईआई को कवर करती है, जिसमें 7.5 लाख रु. तक 75% क्रेडिट गारंटी और ≤ 8 लाख रु. आय पर 10 लाख रु. तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है (पीआईबी पीएम विद्यालक्ष्मी 2026)।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

23. **प्रश्न: 2026 संकलन में स्वीकृत 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' (ओएनओएस) योजना का 3 कैलेंडर वर्षों (2025, 2026 और 2027) के लिए कुल बजटीय आवंटन कितना है, जो इनफ्लिबनेट के माध्यम से 13,000+ शोध जर्नलों की निःशुल्क पहुँच देती है?**
(क) 2,000 करोड़ रुपये
(ख) 6,000 करोड़ रुपये (1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ)
(ग) 10,000 करोड़ रुपये
(घ) 1,500 करोड़ रुपये
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) का परिव्यय 2025–2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

24. **प्रश्न: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित 'पीएम इंटर्नशिप योजना' (शीर्ष 500 कंपनियों में) के तहत 5 वर्षों में कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और इसमें मासिक भत्ता व एकमुश्त अनुदान कितना है?**
(क) 50 लाख युवा; 3,000 रु./माह + 3,000 रु. अनुदान
(ख) 1 करोड़ युवा (आयु 21–24 वर्ष); 5,000 रु./माह भत्ता (4,500 रु. सरकार + 500 रु. कंपनी सीएसआर) तथा 6,000 रु. एकमुश्त अनुदान
(ग) 2 करोड़ युवा; 8,000 रु./माह + 10,000 रु. अनुदान
(घ) 20 लाख युवा; 10,000 रु./माह
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएम इंटर्नशिप योजना (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं (21–24 वर्ष) को 5,000 रु./माह भत्ता और 6,000 रु. एकमुश्त अनुदान देती है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

25. **प्रश्न: 2023–28 के लिए 50,000 करोड़ रुपये के कोष (जिसमें 72% निजी/उद्योग स्रोतों से है) के साथ स्थापित 'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (एएनआरएफ) के शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?**
(क) केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री
(ख) भारत के प्रधानमंत्री (भारत के प्रधानमंत्री)
(ग) नीति आयोग के उपाध्यक्ष
(घ) भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

26. **प्रश्न: 2026 संकलन में स्वीकृत 'इंडिया-एआई मिशन' (इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय) और 'राष्ट्रीय क्वांटम मिशन' (डीएसटी, 2023–2031) का कुल बजटीय परिव्यय क्रमशः कितना है?**
(क) 5,000 करोड़ रु. और 3,000 करोड़ रु.
(ख) 10,371.92 करोड़ रुपये (इंडिया-एआई मिशन) और 6,003.65 करोड़ रुपये (राष्ट्रीय क्वांटम मिशन)
(ग) 15,000 करोड़ रु. और 10,000 करोड़ रु.
(घ) 2,817 करोड़ रु. और 2,481 करोड़ रु.
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** इंडिया-एआई मिशन का परिव्यय 10,371.92 करोड़ रु. और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का परिव्यय 6,003.65 करोड़ रु. है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

27. **प्रश्न: 2026 संकलन में 2,817 करोड़ रुपये के परिव्यय से स्वीकृत 'डिजिटल कृषि मिशन' के तीन मूलभूत डिजिटल स्तंभ कौन-से हैं?**
(क) ई-नाम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पीएम-किसान
(ख) एग्रीस्टैक (किसान रजिस्ट्री/11 करोड़ फार्मर आईडी, ग्राम मानचित्र, फसल सर्वेक्षण), कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली) और मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण
(ग) पीएम फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सुविधा
(घ) नमो ड्रोन दीदी, नैनो यूरिया और मंडी पोर्टल
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** डिजिटल कृषि मिशन (2,817 करोड़ रु.) के तीन स्तंभ एग्रीस्टैक (11 करोड़ फार्मर आईडी), कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

28. **प्रश्न: 2026 संकलन में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय से स्वीकृत 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन' (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन) के तहत कितने किसानों को जोड़ने और कितने जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करने का लक्ष्य है?**
(क) 50 लाख किसान और 5,000 बीआरसी
(ख) 7.5 लाख हेक्टेयर में 1 करोड़ किसान और 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी)
(ग) 2 करोड़ किसान और 20,000 बीआरसी
(घ) 25 लाख किसान और 2,500 बीआरसी
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (2,481 करोड़ रु.) का लक्ष्य 1 करोड़ किसान और 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

29. **प्रश्न: 2026 संकलन में स्वीकृत 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन' (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन) का परिव्यय कितना है और इसके तहत वर्ष 2030–31 तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है?**
(क) 5,000 करोड़ रु.; 50 मिलियन टन
(ख) 10,103 करोड़ रुपये (7 वर्ष); वर्ष 2030–31 तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन 69.7 मिलियन टन करना
(ग) 11,040 करोड़ रु.; 45 मिलियन टन
(घ) 15,000 करोड़ रु.; 80 मिलियन टन
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (10,103 करोड़ रु.) का लक्ष्य 2030–31 तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 69.7 मिलियन टन तक पहुँचाना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

30. **प्रश्न: 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएवाई) को ब्रिक्स विस्तार चरण (2026 संकलन) से कितने वर्षों के लिए और कितने कुल परिव्यय पर विस्तारित किया गया है?**
(क) 3 वर्ष (दिसंबर 2026 तक); 5.90 लाख करोड़ रु.
(ख) 5 वर्ष (ब्रिक्स विस्तार चरण (2026 संकलन) से 31 दिसंबर 2028 तक); 11.80 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय
(ग) 2 वर्ष (दिसंबर 2025 तक); 3.50 लाख करोड़ रु.
(घ) 10 वर्ष (दिसंबर 2033 तक); 20 लाख करोड़ रु.
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएमजीकेएवाई को ब्रिक्स विस्तार चरण (2026 संकलन) से 5 वर्षों (दिसंबर 2028) के लिए 11.80 लाख करोड़ रु. के परिव्यय पर बढ़ाया गया है (पीआईबी आर्थिक समीक्षा विज्ञप्ति)।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

31. **प्रश्न: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 'पीएम-प्रणाम' (प्रधानमंत्री प्रणाम) योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने वाले राज्यों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है?**
(क) 10,000 करोड़ रुपये के अलग बजटीय कोष से
(ख) राज्य द्वारा रासायनिक उर्वरक खपत घटाकर बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% हिस्सा उस राज्य को अनुदान के रूप में वापस दिया जाता है
(ग) प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये राज्य कोष में देकर
(घ) कृषि यंत्रों पर जीएसटी माफ करके
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएम-प्रणाम के तहत राज्य द्वारा बचाई गई रासायनिक उर्वरक सब्सिडी का 50% हिस्सा उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

32. **प्रश्न: पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि) योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं (पथ विक्रेता) को समय पर ऋण चुकाने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त में क्रमशः कितनी कार्यशील पूंजी ऋण राशि दी जाती है?**
(क) 5,000 रु., 10,000 रु. और 25,000 रु.
(ख) 10,000 रु. (प्रथम किस्त), 20,000 रु. (द्वितीय किस्त) और 50,000 रु. (तृतीय किस्त) — 7% ब्याज सब्सिडी के साथ
(ग) 15,000 रु., 30,000 रु. और 60,000 रु.
(घ) 10,000 रु., 25,000 रु. और 1,00,000 रु.
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** पीएम स्वनिधि के तहत पथ विक्रेताओं को 10,000 रु., 20,000 रु. और 50,000 रु. की तीन किस्तों में कार्यशील पूंजी ऋण मिलता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

33. **प्रश्न: 2026 संकलन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी क्षय रोग (टीबी) मरीज़ों के लिए 'निक्षय पोषण योजना' के तहत मिलने वाली मासिक पोषण सहायता राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है?**
(क) 750 रुपये प्रतिमाह
(ख) 1,000 रुपये प्रतिमाह (संपूर्ण उपचार अवधि के लिए)
(ग) 1,500 रुपये प्रतिमाह
(घ) 2,000 रुपये प्रतिमाह
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** 2026 संकलन में निक्षय पोषण योजना की राशि 500 रु. से दोगुनी कर 1,000 रु./माह कर दी गई (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

34. **प्रश्न: सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई को 100% मशीनीकृत करने और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'नमस्ते' (नमस्ते) योजना किन दो मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है?**
(क) जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय मंत्रालय) और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)
(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय
(घ) गृह मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** नमस्ते (नमस्ते) योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

35. **प्रश्न: 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय से देश में 7 'पीएम मित्र' (प्रधानमंत्री मित्र) एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क किन 7 राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं?**
(क) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, असम, ओडिशा और केरल
(ख) तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र
(ग) पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड और त्रिपुरा
(घ) दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, गोवा, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** 7 पीएम मित्र वस्त्र पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किए जा रहे हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

36. **प्रश्न: गृह मंत्रालय के 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' (वीवीपी — परिव्यय 4,800 करोड़ रुपये) के अंतर्गत भारत की उत्तरी सीमा से सटे किन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 2,967 सीमावर्ती गाँवों का विकास किया जा रहा है?**
(क) पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर
(ख) अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड (4 राज्य) और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
(ग) असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मणिपुर
(घ) बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

37. **प्रश्न: उत्तर प्रदेश सरकार की किस प्रमुख योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक प्रवेश तक 6 चरणों में दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है?**
(क) मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना
(ख) मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
(ग) स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
(घ) रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि 15,000 रु. से बढ़ाकर 25,000 रु. कर दी गई है (आईयूसी अकादमी)।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

38. **प्रश्न: उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान) के तहत शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु कितने रुपये तक का ब्याज-मुक्त और गारंटी-मुक्त ऋण दिया जाता है?**
(क) 2 लाख रुपये तक
(ख) 5 लाख रुपये तक (प्रतिवर्ष 1 लाख युवा / 10 वर्षों में 10 लाख युवा उद्यमी)
(ग) 10 लाख रुपये तक
(घ) 1 लाख रुपये तक
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान) के तहत 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है (आईयूसी अकादमी)।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

39. **प्रश्न: 17 2026 संकलन को ओडिशा में शुभारंभ की गई 'सुभद्रा योजना' (सुभद्रा योजना) के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?**
(क) 3 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रतिमाह
(ख) 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये (5,000–5,000 रुपये की दो किस्तों में — कुल 50,000 रुपये प्रति महिला)
(ग) 2,500 रुपये प्रतिमाह
(घ) 25,000 रुपये एकमुश्त विवाह अनुदान
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** ओडिशा की सुभद्रा योजना के तहत 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रु. (5,000 रु. की 2 किस्तें = कुल 50,000 रु.) दिए जाते हैं (पीआईबी नवंबर 2026)।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

40. **प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नाम' (माँ के नाम वृक्षारोपण) अभियान का शुभारंभ किया, जिसके तहत देश भर में 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए?**
(क) 22 2026 संकलन (पृथ्वी दिवस)
(ख) 5 2026 संकलन (विश्व पर्यावरण दिवस)
(ग) 1 2026 संकलन (वन महोत्सव)
(घ) 2 2026 संकलन (गांधी जयंती)
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** 5 2026 संकलन (विश्व पर्यावरण दिवस) को 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान शुरू किया गया (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

41. **प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026–27 में घोषित 'विकसित भारत ग्राम रोज़गार मिशन' के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के गारंटीकृत रोज़गार का प्रावधान किया गया है तथा इसमें केंद्र का अंश कितना है?**
(क) 100 दिन; 60,000 करोड़ रुपये
(ख) 125 दिन प्रतिवर्ष; 95,692 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश (कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक; 50% क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा)
(ग) 150 दिन; 1,20,000 करोड़ रुपये
(घ) 120 दिन; 86,000 करोड़ रुपये
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** केंद्रीय बजट 2026–27 में विकसित भारत ग्राम रोज़गार मिशन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश (कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक) आवंटित किया गया है, जो ग्रामीण रोज़गार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रतिवर्ष करता है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

42. **प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026–27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुल बजटीय आवंटन तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास का संयुक्त आवंटन क्रमशः कितना है?**
(क) 1,50,000 करोड़ रुपये और 3.20 लाख करोड़ रुपये
(ख) 1,97,023 करोड़ रुपये (21% वृद्धि) तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास का संयुक्त आवंटन 4.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक
(ग) 2,55,234 करोड़ रुपये और 5.01 लाख करोड़ रुपये
(घ) 1,41,000 करोड़ रुपये और 2.80 लाख करोड़ रुपये
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** केंद्रीय बजट 2026–27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,97,023 करोड़ रुपये (+21%) और कृषि मंत्रालय को 1.41 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास का संयुक्त बजट 4.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

43. **प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026–27 (शिक्षा मंत्रालय आवंटन: 1.39 लाख करोड़ रुपये) में सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु कितने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स प्रयोगशालाएँ स्थापित करने तथा अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई?**
(क) 5,000 विद्यालय व 100 महाविद्यालय; 20,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ
(ख) 15,000 विद्यालय व 500 महाविद्यालय; अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का 10,000 से 50,000 तक विस्तार
(ग) 10,000 विद्यालय व 250 महाविद्यालय; 30,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ
(घ) 25,000 विद्यालय व 1,000 महाविद्यालय; 75,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** वर्ष 2030 तक 20 लाख रोज़गार सृजित करने हेतु बजट 2026–27 में 15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में सृजनात्मक प्रयोगशालाएँ, 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ और 5 विश्वविद्यालय नगर स्थापित करने की घोषणा की गई (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

44. **प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026–27 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 तथा 53 मंत्रालयों के समग्र लैंगिक बजट (जेंडर बजट) के लिए क्रमशः कितना आवंटन किया गया है?**
(क) 89,000 करोड़ रु., 10,000 करोड़ रु. और 3.50 लाख करोड़ रु.
(ख) 1,06,530.42 करोड़ रु. (स्वास्थ्य), 18,625.05 करोड़ रु. (प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0) और 5.01 लाख करोड़ रु. (लैंगिक बजट)
(ग) 1,20,000 करोड़ रु., 25,000 करोड़ रु. और 4.20 लाख करोड़ रु.
(घ) 95,692 करोड़ रु., 13,670 करोड़ रु. और 6.00 लाख करोड़ रु.
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** केंद्रीय बजट 2026–27 में स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530.42 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 को 18,625.05 करोड़ रुपये और लैंगिक बजट को 5.01 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

45. **प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026–27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (आवंटन: 24,566 करोड़ रुपये) तथा कृषि क्षेत्र (आवंटन: 1.41 लाख करोड़ रुपये) के सशक्तिकरण हेतु किन नई पहलों की घोषणा की गई?**
(क) प्रथम चरण समूह योजना और राष्ट्रीय कृषि बाज़ार 1.0
(ख) 10,000 करोड़ रुपये का लघु उद्यम विकास कोष व कॉर्पोरेट मित्र; तथा कृषि में 'भारत-विस्तार' डिजिटल मंच एवं 'बीज अधिनियम 2026'
(ग) फेम-प्रथम और मृदा स्वास्थ्य कार्ड 1.0
(घ) स्टैंड-अप इंडिया 1.0 और पीएम-किसान 1.0
सही उत्तर: (ख) | **व्याख्या:** बजट 2026–27 में सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विकास कोष, कॉर्पोरेट मित्र और 200 विरासत शिल्प केंद्रों का पुनरुद्धार तथा कृषि क्षेत्र में भारत-विस्तार डिजिटल मंच और बीज अधिनियम 2026 प्रस्तुत किए गए (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

त्वरित पुनरावलोकन बिंदु (65 सत्यापित केंद्रीय बजट 2026–27 एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ सार-संग्रह बिंदु)

1. **पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना** (**13 2026 संकलन**, परिव्यय **75,021 करोड़ रु.**) के तहत **1 करोड़ घरों** में रूफशीर्ष सोलर और प्रतिमाह **300 यूनिट मुफ़्त बिजली** दी जाती है (पीआईबी पीएम सूर्य घर 2026)।

2. **पीएम सूर्य घर योजना** में प्रत्यक्ष सब्सिडी **1 किलोवाट पर 30,000 रु., 2 किलोवाट पर 60,000 रु.** और **3 किलोवाट या अधिक पर अधिकतम 78,000 रु.** निर्धारित है (पीआईबी पीएम सूर्य घर विवरण)।

3. मार्च 2026 तक **पीएम सूर्य घर योजना** के तहत देश में **26.19 लाख से अधिक रूफशीर्ष सोलर सिस्टम** लगाए जा चुके हैं और **17,967.53 करोड़ रु. की सब्सिडी** दी जा चुकी है (पीआईबी मार्च 2026)।

4. **पीएम-कुसुम योजना** (परिव्यय **34,422 करोड़ रु.**) के 3 घटकों (क, ख, ग) के माध्यम से कृषि क्षेत्र में **30.8 गीगावाट सौर क्षमता** का लक्ष्य है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

5. **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** (परिव्यय **19,744 करोड़ रु.**) का लक्ष्य वर्ष **2030 तक प्रतिवर्ष 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन उत्पादन** और 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

6. **पीएम ई-ड्राइव योजना** (2026 संकलन, परिव्यय **10,900 करोड़ रु.**, भारी उद्योग मंत्रालय) ने फेम-द्वितीय का स्थान लिया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

7. **पीएम आवास योजना – शहरी 2.0 (2024–29)** के तहत **10 लाख करोड़ रु. के निवेश** (2.30 लाख करोड़ रु. केंद्रीय सहायता) से **1 करोड़ शहरी मकान** बनाए जाएँगे (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

8. **पीएम आवास योजना – ग्रामीण विस्तार (2024–29)** के तहत **3,06,137 करोड़ रु.** से **2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घर** (मैदानी 1.20 लाख रु. / पहाड़ी 1.30 लाख रु.) बनाए जा रहे हैं (पीआईबी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विज्ञप्ति)।

9. **पीएम ग्राम सड़क योजना – चरण चतुर्थ** (परिव्यय **70,125 करोड़ रु.**) के तहत **25,000 बसावटों** को जोड़ने हेतु **62,500 किमी सड़कें** बनाई जाएँगी (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

10. **आयुष्मान भारत पीएम-जय** (**23 सितंबर 2018** को राँची से शुभारंभ) प्रति परिवार प्रतिवर्ष **5 लाख रुपये** का कैशलेस उपचार देती है (पीआईबी स्वास्थ्य नोट)।

11. **आयुष्मान वय वंदना** (**29 2026 संकलन** को शुभारंभ) के तहत **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** को बिना किसी आय सीमा के **5 लाख रु./वर्ष** का स्वास्थ्य कवर मिलता है (पीआईबी अक्टूबर 2026)।

12. **आयुष्मान वय वंदना** से **4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक** लाभान्वित हैं और अक्टूबर 2026 तक **23.46 लाख अस्पताल दाखिले** दर्ज हुए (पीआईबी अक्टूबर 2026)।

13. **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)** के तहत प्रत्येक नागरिक को **14-अंकीय आभा आईडी** जारी की जाती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

14. **यू-विन (यू-विन) पोर्टल** गर्भवती महिलाओं और बच्चों के **12 टीकों** का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

15. **राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन** (1 जुलाई 2023, शहडोल) का लक्ष्य **2047** तक रोग उन्मूलन हेतु **7 करोड़ लोगों (0–40 वर्ष)** की जांच करना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

16. 2026 संकलन में सभी क्षय रोग (टीबी) मरीज़ों के लिए **निक्षय पोषण योजना** की सहायता राशि 500 रु. से दोगुनी कर **1,000 रुपये प्रतिमाह** कर दी गई (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

17. **पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0)** में प्रथम संतान पर **5,000 रु.** और दूसरी संतान **बालिका होने पर 6,000 रु.** दिए जाते हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

18. **जल जीवन मिशन (हर घर जल)** प्रत्येक ग्रामीण घर में **55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)** शुद्ध नल जल पहुँचाता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

19. **लखपति दीदी पहल** (ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) का लक्ष्य बढ़ाकर **3 करोड़ एसएचजी महिलाएँ** (वार्षिक शुद्ध आय **≥ 1,00,000 रु.**) कर दिया गया है (पीआईबी लखपति दीदी नवंबर 2026)।

20. **नमो ड्रोन दीदी योजना** (परिव्यय **1,261 करोड़ रु.**, कृषि मंत्रालय) में **15,000 महिला एसएचजी** को ड्रोन खरीद पर **80% सब्सिडी (अधिकतम 8 लाख रु.)** मिलती है (पीआईबी विकसित भारत विज्ञप्ति)।

21. **मिशन शक्ति** के दो उप-घटक हैं: **'संबल'** (वन स्टॉप सेंटर, 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत) और **'सामर्थ्य'** (पीएमएमवीवाई, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास) (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

22. **स्वामित्व योजना** (**24 अप्रैल 2020**, पंचायती राज मंत्रालय) ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण आबादी भूमि के कानूनी **संपत्ति कार्ड** जारी करती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

23. **एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)** (**1 अप्रैल 2025** से प्रभावी, **डॉ. टी.वी. सोमनाथन समिति**) में 25 वर्ष सेवा पर **अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50%** सुनिश्चित पेंशन मिलती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

24. **यूपीएस** में **पारिवारिक पेंशन 60%**, **न्यूनतम पेंशन 10,000 रु./माह** (10+ वर्ष सेवा) और **सरकारी अंशदान 18.5%** (कर्मचारी 10%) है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

25. **एनपीएस वात्सल्य योजना** (**18 2026 संकलन**, पीएफआरडीए) में **0–18 वर्ष के नाबालिगों** हेतु न्यूनतम **1,000 रु./वर्ष** से पेंशन खाता खोला जाता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

26. **पीएम विश्वकर्मा योजना** (**17 सितंबर 2023**, परिव्यय **13,000 करोड़ रु.**, एमएसएमई मंत्रालय) **18 पारंपरिक व्यवसायों** को **15,000 रु. टूलकिट** और **5% ब्याज पर 3 लाख रु. ऋण** देती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

27. **पीएम-जनमन (पीएम-जनमन)** (**15 नवंबर 2023**, परिव्यय **24,104 करोड़ रु.**) 18 राज्यों व अंडमान के 75 **पीवीटीजी** को **9 मंत्रालयों की 11 सुविधाओं** से संतृप्त करती है (पीआईबी जुलाई 2026)।

28. **धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)** (**2 2026 संकलन**, परिव्यय **79,156 करोड़ रु.**) **63,843 जनजातीय-बहुल गाँवों (5+ करोड़ आबादी)** को 17 मंत्रालयों की 25 योजनाओं से जोड़ता है (पीआईबी नवंबर 2026)।

29. **पीएम मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** की 4 ऋण श्रेणियाँ हैं: **शिशु (50 हज़ार तक)**, **किशोर (50 हज़ार से 5 लाख)**, **तरुण (5 लाख से 10 लाख)** और **तरुण प्लस (10 लाख से 20 लाख)** (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

30. **पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)** ने **28 2026 संकलन को 10 वर्ष** पूर्ण किए; इसमें **53.1+ करोड़ खाते**, **10,000 रु. ओवरड्राफ्ट** और **2 लाख रु. दुर्घटना बीमा** है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

31. **पीएमजेजेबीवाई (18–50 वर्ष)** में **436 रु./वर्ष** पर 2 लाख रु. जीवन बीमा और **पीएमएसबीवाई (18–70 वर्ष)** में **20 रु./वर्ष** पर 2 लाख रु. दुर्घटना बीमा मिलता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

32. **स्टैंड-अप इंडिया योजना** में प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम **1 अनुसूचित जाति/जनजाति और 1 महिला उद्यमी** को **10 लाख रु. से 1 करोड़ रु.** तक का ऋण दिया जाता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

33. **पीएम स्वनिधि योजना** में शहरी पथ विक्रेताओं को **10,000 रु. → 20,000 रु. → 50,000 रु.** के 3 चरणों में कार्यशील पूंजी ऋण (7% ब्याज सब्सिडी सहित) मिलता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

34. **पीएम विद्यालक्ष्मी योजना** (**6 2026 संकलन**, परिव्यय **3,600 करोड़ रु.**) **860 शीर्ष संस्थानों** में **7.5 लाख रु. तक 75% गारंटी** और **10 लाख रु. तक 3% ब्याज छूट** (आय ≤ 8 लाख रु.) देती है (पीआईबी जुलाई 2026)।

35. **वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)** (परिव्यय **6,000 करोड़ रु.**, 2025–27) **इनफ्लिबनेट** के माध्यम से **1.8 करोड़ छात्रों/शोधकर्ताओं** को **13,000+ शोध जर्नलों** की निःशुल्क पहुँच देती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

36. **पीएम इंटर्नशिप योजना** (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) **शीर्ष 500 कंपनियों** में **1 करोड़ युवाओं (21–24 वर्ष)** को **5,000 रु./माह भत्ता** + **6,000 रु. एकमुश्त अनुदान** देती है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

37. **प्रधानमंत्री के रोज़गार एवं कौशल पैकेज** में **5 योजनाएँ** शामिल हैं जिनका 5 वर्षों के लिए कुल परिव्यय **2 लाख करोड़ रुपये** (4.1 करोड़ युवाओं हेतु) है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

38. **आईटीआई उन्नयन योजना** (परिव्यय **60,000 करोड़ रु.**) के तहत हब-एंड-स्पोक आदर्श में **1,000 सरकारी आईटीआई** का उन्नयन कर **20 लाख युवाओं** को प्रशिक्षित किया जाएगा (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

39. **पीएम श्री स्कूल (प्रधानमंत्री श्री)** (परिव्यय **27,360 करोड़ रु.**) के तहत **14,500+ विद्यालयों** को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

40. **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)** का कोष **50,000 करोड़ रुपये (2023–28)** है और इसके शासी बोर्ड के **अध्यक्ष प्रधानमंत्री** हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

41. **इंडिया-एआई मिशन** (इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय, परिव्यय **10,371.92 करोड़ रु.**) के तहत **18,000+ जीपीयू** और **एआई-कोष** डेटासेट प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

42. **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन** (डीएसटी, परिव्यय **6,003.65 करोड़ रु.**, 2023–31) के 4 विषयगत केंद्र **भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली** में हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

43. **बायो-ई3 नीति** (2026 संकलन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग) का अर्थ **अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिए जैव प्रौद्योगिकी** है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

44. **डिजिटल कृषि मिशन** (परिव्यय **2,817 करोड़ रु.**, 2026 संकलन) के तहत **एग्रीस्टैक (11 करोड़ फार्मर आईडी)** और **कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली** बनाए जा रहे हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

45. **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन)** (परिव्यय **2,481 करोड़ रु.**, 2026 संकलन) **1 करोड़ किसानों** को जोड़ता है और **10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी)** स्थापित करता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

46. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन)** (परिव्यय **10,103 करोड़ रु.**) का लक्ष्य 2030–31 तक तिलहन उत्पादन **39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन** करना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

47. **क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम)** (परिव्यय **1,765.67 करोड़ रु.**, एडीबी समर्थित) के तहत देश में **9 क्लीन प्लांट सेंटर (सीपीसी)** स्थापित किए जा रहे हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

48. **पीएम-किसान** (24 फरवरी 2019, गोरखपुर से प्रारंभ) भूमिधारक किसान परिवारों को **6,000 रुपये प्रतिवर्ष** (2,000 रु. की 3 किस्तें) देती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

49. **पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)** में किसानों की प्रीमियम दरें **रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%** और **वाणिज्यिक/बागवानी के लिए 5%** हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

50. **पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)** को **5 वर्षों (2026 संकलन – दिसंबर 2028)** के लिए **11.80 लाख करोड़ रु.** के परिव्यय पर बढ़ाया गया है (**81.35 करोड़ लाभार्थी**) (पीआईबी आर्थिक समीक्षा विज्ञप्ति)।

★ 51. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना** के तहत **पैक्स** स्तर पर **700 लाख मीस्मरण सूत्र टन (70 एमएमटी)** भंडारण क्षमता बनाई जा रही है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

52. **पीएम-प्रणाम** रासायनिक उर्वरक घटाने वाले राज्यों को **बचाई गई सब्सिडी का 50% अनुदान** देती है, और **यूरिया गोल्ड सल्फर-लेपित यूरिया (37% नाइट्रोजन + 17% गंधक (सल्फर))** है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

53. **नमस्ते (नमस्ते)** सीवर/सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई हेतु **सामाजिक न्याय मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय** की संयुक्त योजना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

54. 7 **पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मित्र) वस्त्र पार्क (4,445 करोड़ रु.) तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र** में स्थित हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

55. **वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी — 4,800 करोड़ रु.) अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश** के 2,967 सीमावर्ती गाँवों का विकास करता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

56. **मिष्टी (मिष्टी)** तटीय **मैंग्रोव वनों** के संरक्षण की योजना है, जबकि **अमृत धरोहर रामसर आर्द्रभूमियों (आर्द्रभूमि)** के संरक्षण की योजना है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

57. **उत्तर प्रदेश** में **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** की राशि बढ़ाकर **25,000 रुपये** (6 चरणों में) कर दी गई है और **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान** में युवाओं को **5 लाख रु. तक ब्याज-मुक्त ऋण** मिलता है (आईयूसी अकादमी)।

58. **ओडिशा की सुभद्रा योजना** (17 2026 संकलन) में महिलाओं (21–60 वर्ष) को **5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रु. (5,000 रु. की 2 किस्तें = कुल 50,000 रु.)** दिए जाते हैं (पीआईबी नवंबर 2026)।

59. **मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना** में **1,250 रु./माह**, **महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहीण** में **1,500 रु./माह** और **छत्तीसगढ़ की महतारी वंदना** में **1,000 रु./माह** दिए जाते हैं (आईयूसी अकादमी)।

60. **'एक पेड़ माँ के नाम' (माँ के नाम वृक्षारोपण)** अभियान **5 2026 संकलन (विश्व पर्यावरण दिवस)** को शुरू हुआ, जिसके तहत देश भर में **100 करोड़ से अधिक पौधे** लगाए गए (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

61. **केंद्रीय बजट 2026–27 (1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत)** में **ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,97,023 करोड़ रुपये (+21%)**, **कृषि मंत्रालय को 1.41 लाख करोड़ रुपये** (संयुक्त ग्रामीण व कृषि बजट **4.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक**), **गृह मंत्रालय को 2,55,234 करोड़ रुपये** तथा **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2,39,521 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

62. बजट 2026–27 के **'विकसित भारत ग्राम रोज़गार मिशन'** का कुल परिव्यय **1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक (95,692 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश)** है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **प्रतिवर्ष 125 दिनों का गारंटीकृत रोज़गार** और **ग्राम पंचायतों के माध्यम से 50% विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन** प्रदान करता है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

63. **केंद्रीय बजट 2026–27** में **स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530.42 करोड़ रुपये (बायो-फार्मा शक्ति मिशन** सहित) और **प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 को 18,625.05 करोड़ रुपये** मिले, जबकि **जल जीवन मिशन** ने **81.31% ग्रामीण नल जल कवरेज** और **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** ने **99.7% बसावट संपर्क** प्राप्त किया (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

64. बजट 2026–27 के **1.39 लाख करोड़ रुपये के शिक्षा आवंटन** के तहत **15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक्स प्रयोगशालाएँ**, **50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ** और **5 विश्वविद्यालय नगर** स्थापित किए जा रहे हैं (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

65. **लैंगिक बजट 2026–27** 53 मंत्रालयों में बढ़कर **5.01 लाख करोड़ रुपये** हो गया (**शी-मार्ट** सहित), जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु **24,566 करोड़ रुपये + 10,000 करोड़ रुपये का लघु उद्यम विकास कोष**, **कॉर्पोरेट मित्र**, **भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0**, **भारत-विस्तार** और **बीज अधिनियम 2026** प्रारंभ किए गए (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

व्यापक विश्लेषणात्मक तथ्य सारणी एवं बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास

क्र.	प्रमुख विषय / क्षेत्र	मुख्य प्रावधान / सूचकांक / मिशन	सत्यापित आधिकारिक तथ्य एवं परीक्षा बिंदु
1	योजना का नाम	पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) — 2026 संकलन; 75,021 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
2	योजना का नाम	पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम)	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) — 2019 (2026 तक विस्तारित); 34,422 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
3	योजना का नाम	राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) — जनवरी 2023; 19,744 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
4	योजना का नाम	पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव)	भारी उद्योग मंत्रालय — 2026 संकलन; 10,900 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
5	योजना का नाम	पीएम आवास योजना – शहरी 2.0	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय — 2026 संकलन (2024–29); 2.30 लाख करोड़ रु. केंद्रीय सहायता (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
6	योजना का नाम	पीएम आवास योजना – ग्रामीण (विस्तार)	ग्रामीण विकास मंत्रालय — 2026 संकलन (2024–29); 3,06,137 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
7	योजना / पोर्टल का नाम	आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक विस्तार)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए) — 29 2026 संकलन; 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक (4.5 करोड़ परिवार) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
8	योजना / पोर्टल का नाम	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय — सितंबर 2021; 1,600 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
9	योजना / पोर्टल का नाम	राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन	स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय — 1 जुलाई 2023; लक्ष्य वर्ष: 2047 (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
10	योजना / पोर्टल का नाम	निक्षय पोषण योजना (टीबी मुक्त भारत)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय — 2026 संकलन में राशि दोगुनी (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
11	योजना / पोर्टल का नाम	पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय — मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
12	योजना / पोर्टल का नाम	जल जीवन मिशन (हर घर जल)	जल शक्ति मंत्रालय — 15 अगस्त 2019; 3.60 लाख करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
13	योजना का नाम	लखपति दीदी पहल	ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) — लक्ष्य: 3 करोड़ एसएचजी महिलाएँ (2 करोड़ से बढ़ाया गया) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
14	योजना का नाम	नमो ड्रोन दीदी योजना	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — 15,000 महिला एसएचजी; परिव्यय 1,261 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
15	योजना का नाम	मिशन शक्ति (संबल एवं सामर्थ्य)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय — सुरक्षा (संबल) एवं सशक्तिकरण (सामर्थ्य) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
16	योजना का नाम	सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना)	वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास — 10 वर्ष से कम आयु की बालिका (अधिकतम 2 बालिकाएँ) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
17	योजना का नाम	स्वामित्व योजना (स्वामित्व)	पंचायती राज मंत्रालय — 24 अप्रैल 2020 को शुभारंभ (केंद्रीय क्षेत्रक) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
18	योजना का नाम	मनरेगा (मनरेगा)	ग्रामीण विकास मंत्रालय — वैधानिक अधिनियम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
19	योजना का नाम	एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)	वित्त मंत्रालय — 24 2026 संकलन को स्वीकृत; 1 अप्रैल 2025 से लागू (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
20	योजना का नाम	एनपीएस वात्सल्य योजना	वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए — 18 2026 संकलन (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))

क्र.	प्रमुख विषय / क्षेत्र	मुख्य प्रावधान / सूचकांक / मिशन	सत्यापित आधिकारिक तथ्य एवं परीक्षा बिंदु
21	योजना का नाम	पीएम विश्वकर्मा योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) — 17 सितंबर 2023; 13,000 करोड़ रु. (2023–28) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
22	योजना का नाम	पीएम-जनमन (पीएम-जनमन)	जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय) — 15 नवंबर 2023; 24,104 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
23	योजना का नाम	धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)	जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय) — 2 2026 संकलन; 79,156 करोड़ रु. (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
24	योजना का नाम	पीएम मुद्रा योजना ('तरुण प्लस' विस्तार)	वित्त मंत्रालय — 8 अप्रैल 2015 (2026 संकलन में विस्तारित) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
25	योजना / मिशन का नाम	पीएम विद्यालक्ष्मी योजना	शिक्षा मंत्रालय — 3,600 करोड़ रु. (2024–25 से 2030–31) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
26	योजना / मिशन का नाम	वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)	शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट) — 6,000 करोड़ रु. (2025–2027) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
27	योजना / मिशन का नाम	पीएम इंटर्नशिप योजना	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) — 2 लाख करोड़ रु. के पैकेज का भाग (5 वर्ष) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
28	योजना / मिशन का नाम	1,000 आईटीआई उन्नयन योजना	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय — 60,000 करोड़ रु. (5 वर्ष) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
29	योजना / मिशन का नाम	अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) — 50,000 करोड़ रु. (2023–28) + 1 लाख करोड़ अनुसंधान एवं विकास पूल (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
30	योजना / मिशन का नाम	इंडिया-एआई मिशन एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन	इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम) — 10,371.92 करोड़ रु. (इंडिया-एआई) एवं 6,003.65 करोड़ रु. (राष्ट्रीय क्वांटम मिशन) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
31	योजना / मिशन का नाम	डिजिटल कृषि मिशन	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — 2,817 करोड़ रु. (2026 संकलन में स्वीकृत) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
32	योजना / मिशन का नाम	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — 2,481 करोड़ रु. (2026 संकलन में स्वीकृत) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
33	योजना / मिशन का नाम	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — 10,103 करोड़ रु. (2024–25 से 2030–31) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
34	योजना / मिशन का नाम	क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम)	कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) — 1,765.67 करोड़ रु. (एडीबी के सहयोग से) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
35	योजना / मिशन का नाम	पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — 24 फरवरी 2019 (100% केंद्रीय क्षेत्रक) (पत्र सूचना कार्यालय (PIB))

बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास (कथन-I एवं कथन-II परीक्षण)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना):** योजना का नाम के संदर्भ में पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना का सही विवरण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) है। **कथन-II (पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम)):** योजना का नाम के संदर्भ में पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम) का सही विवरण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)**) और कथन-II (**पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन):** योजना का नाम के संदर्भ में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का सही विवरण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) है। **कथन-II (पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव)):** योजना का नाम के संदर्भ में पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव) का सही विवरण भारी उद्योग मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)**) और कथन-II (**पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव): भारी उद्योग मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (पीएम आवास योजना – शहरी 2.0):** योजना का नाम के संदर्भ में पीएम आवास योजना – शहरी 2.0 का सही विवरण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है। **कथन-II (पीएम आवास योजना – ग्रामीण (विस्तार)):** योजना का नाम के संदर्भ में पीएम आवास योजना – ग्रामीण (विस्तार) का सही विवरण ग्रामीण विकास मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**पीएम आवास योजना – शहरी 2.0: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**) और कथन-II (**पीएम आवास योजना – ग्रामीण (विस्तार): ग्रामीण विकास मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक विस्तार)):** योजना / पोर्टल का नाम के संदर्भ में आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक विस्तार) का सही विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए) है। **कथन-II (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)):** योजना / पोर्टल का नाम के संदर्भ में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का सही विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक विस्तार): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए)**) और कथन-II (**आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन):** योजना / पोर्टल का नाम के संदर्भ में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का सही विवरण स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय है। **कथन-II (निक्षय पोषण योजना (टीबी मुक्त भारत)):** योजना / पोर्टल का नाम के संदर्भ में निक्षय पोषण योजना (टीबी मुक्त भारत) का सही विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन: स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय**) और कथन-II (**निक्षय पोषण योजना (टीबी मुक्त भारत): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0)):** योजना / पोर्टल का नाम के संदर्भ में पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0) का सही विवरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। **कथन-II (जल जीवन मिशन (हर घर जल)):** योजना / पोर्टल का नाम के संदर्भ में जल जीवन मिशन (हर घर जल) का सही विवरण जल शक्ति मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**) और कथन-II (**जल जीवन मिशन (हर घर जल): जल शक्ति मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (लखपति दीदी पहल):** योजना का नाम के संदर्भ में लखपति दीदी पहल का सही विवरण ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) है। **कथन-II (नमो ड्रोन दीदी योजना):** योजना का नाम के संदर्भ में नमो ड्रोन दीदी योजना का सही विवरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**लखपति दीदी पहल: ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)**) और कथन-II (**नमो ड्रोन दीदी योजना: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (मिशन शक्ति (संबल एवं सामर्थ्य)):** योजना का नाम के संदर्भ में मिशन शक्ति (संबल एवं सामर्थ्य) का सही विवरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। **कथन-II (सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना)):** योजना का नाम के संदर्भ में सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना) का सही विवरण वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**मिशन शक्ति (संबल एवं सामर्थ्य): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**) और कथन-II (**सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना): वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (स्वामित्व योजना (स्वामित्व)):** योजना का नाम के संदर्भ में स्वामित्व योजना (स्वामित्व) का सही विवरण पंचायती राज मंत्रालय है। **कथन-II (मनरेगा (मनरेगा)):** योजना का नाम के संदर्भ में मनरेगा (मनरेगा) का सही विवरण ग्रामीण विकास मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**स्वामित्व योजना (स्वामित्व): पंचायती राज मंत्रालय**) और कथन-II (**मनरेगा (मनरेगा): ग्रामीण विकास मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)):** योजना का नाम के संदर्भ में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का सही विवरण वित्त मंत्रालय है। **कथन-II (एनपीएस वात्सल्य योजना):** योजना का नाम के संदर्भ में एनपीएस वात्सल्य योजना का सही विवरण वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस): वित्त मंत्रालय**) और कथन-II (**एनपीएस वात्सल्य योजना: वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (पीएम विश्वकर्मा योजना):** योजना का नाम के संदर्भ में पीएम विश्वकर्मा योजना का सही विवरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) है। **कथन-II (पीएम-जनमन (पीएम-जनमन)):** योजना का नाम के संदर्भ में पीएम-जनमन (पीएम-जनमन) का सही विवरण जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**पीएम विश्वकर्मा योजना: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)**) और कथन-II (**पीएम-जनमन (पीएम-जनमन): जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)):** योजना का नाम के संदर्भ में धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए) का सही विवरण जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय) है। **कथन-II (पीएम मुद्रा योजना ('तरुण प्लस' विस्तार)):** योजना का नाम के संदर्भ में पीएम मुद्रा योजना ('तरुण प्लस' विस्तार) का सही विवरण वित्त मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए): जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय)**) और कथन-II (**पीएम मुद्रा योजना ('तरुण प्लस' विस्तार): वित्त मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (पीएम विद्यालक्ष्मी योजना):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का सही विवरण शिक्षा मंत्रालय है। **कथन-II (वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) का सही विवरण शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: शिक्षा मंत्रालय**) और कथन-II (**वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस): शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (पीएम इंटर्नशिप योजना):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में पीएम इंटर्नशिप योजना का सही विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) है। **कथन-II (1,000 आईटीआई उन्नयन योजना):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में 1,000 आईटीआई उन्नयन योजना का सही विवरण कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**पीएम इंटर्नशिप योजना: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)**) और कथन-II (**1,000 आईटीआई उन्नयन योजना: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) का सही विवरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) है। **कथन-II (इंडिया-एआई मिशन एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में इंडिया-एआई मिशन एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का सही विवरण इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)**) और कथन-II (**इंडिया-एआई मिशन एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन: इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (डिजिटल कृषि मिशन):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में डिजिटल कृषि मिशन का सही विवरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। **कथन-II (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन)):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन) का सही विवरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**डिजिटल कृषि मिशन: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**) और कथन-II (**राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन)):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन) का सही विवरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। **कथन-II (क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम)):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम) का सही विवरण कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**) और कथन-II (**क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम): कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का सही विवरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। **कथन-II (पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)):** योजना / मिशन का नाम के संदर्भ में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का सही विवरण उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**) और कथन-II (**पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई): उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)।

अतिरिक्त उच्च-स्तरीय तुलनात्मक अभ्यास प्रश्नोत्तरी

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (B) भारी उद्योग मंत्रालय (C) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (D) ग्रामीण विकास मंत्रालय **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)** है। विशेष तथ्य: 2026 संकलन; 75,021 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) भारी उद्योग मंत्रालय (B) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (C) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (D) ग्रामीण विकास मंत्रालय **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम-कुसुम योजना (पीएम-कुसुम)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)** है। विशेष तथ्य: 2019 (2026 तक विस्तारित); 34,422 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) भारी उद्योग मंत्रालय (B) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (C) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (D) ग्रामीण विकास मंत्रालय **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)** है। विशेष तथ्य: जनवरी 2023; 19,744 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (C) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए) (D) भारी उद्योग मंत्रालय **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **भारी उद्योग मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 2026 संकलन; 10,900 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम आवास योजना – शहरी 2.0'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (C) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए) (D) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम आवास योजना – शहरी 2.0'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 2026 संकलन (2024–29); 2.30 लाख करोड़ रु. केंद्रीय सहायता। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम आवास योजना – ग्रामीण (विस्तार)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए) (B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (C) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (D) स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम आवास योजना – ग्रामीण (विस्तार)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **ग्रामीण विकास मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 2026 संकलन (2024–29); 3,06,137 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. 'योजना / पोर्टल का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक विस्तार)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (B) स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय (C) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए) (D) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'आयुष्मान वय वंदना (70+ वरिष्ठ नागरिक विस्तार)'** (योजना / पोर्टल का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचए)** है। विशेष तथ्य: 29 2026 संकलन; 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक (4.5 करोड़ परिवार)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. 'योजना / पोर्टल का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय (B) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (C) जल शक्ति मंत्रालय (D) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)'** (योजना / पोर्टल का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: सितंबर 2021; 1,600 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. 'योजना / पोर्टल का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय (B) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (D) जल शक्ति मंत्रालय **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन'** (योजना / पोर्टल का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **स्वास्थ्य एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 1 जुलाई 2023; लक्ष्य वर्ष: 2047। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. 'योजना / पोर्टल का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'निक्षय पोषण योजना (टीबी मुक्त भारत)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (B) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (C) जल शक्ति मंत्रालय (D) ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'निक्षय पोषण योजना (टीबी मुक्त भारत)'** (योजना / पोर्टल का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 2026 संकलन में राशि दोगुनी। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. 'योजना / पोर्टल का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) जल शक्ति मंत्रालय (B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) (C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (D) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई 2.0)'** (योजना / पोर्टल का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. 'योजना / पोर्टल का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'जल जीवन मिशन (हर घर जल)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) ग्रामीण विकास
मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) (B) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (D) जल शक्ति मंत्रालय **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'जल जीवन मिशन (हर घर जल)'** (योजना / पोर्टल का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **जल शक्ति मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 15 अगस्त 2019; 3.60 लाख करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'लखपति दीदी पहल'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) (B) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (D) वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'लखपति दीदी पहल'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **ग्रामीण विकास मंत्रालय (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)** है। विशेष तथ्य: लक्ष्य: 3 करोड़ एसएचजी महिलाएँ (2 करोड़ से बढ़ाया गया)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'नमो ड्रोन दीदी योजना'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (B) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (C) वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास (D) पंचायती राज मंत्रालय **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'नमो ड्रोन दीदी योजना'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 15,000 महिला एसएचजी; परिव्यय 1,261 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'मिशन शक्ति (संबल एवं सामर्थ्य)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास (B) पंचायती राज मंत्रालय (C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (D) ग्रामीण विकास मंत्रालय **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'मिशन शक्ति (संबल एवं सामर्थ्य)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: सुरक्षा (संबल) एवं सशक्तिकरण (सामर्थ्य)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 61. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) पंचायती राज मंत्रालय (B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (C) वित्त मंत्रालय (D) वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **वित्त मंत्रालय / महिला एवं बाल विकास** है। विशेष तथ्य: 10 वर्ष से कम आयु की बालिका (अधिकतम 2 बालिकाएँ)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 62. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'स्वामित्व योजना (स्वामित्व)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) पंचायती राज मंत्रालय (B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (C) वित्त मंत्रालय (D) वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'स्वामित्व योजना (स्वामित्व)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **पंचायती राज मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 24 अप्रैल 2020 को शुभारंभ (केंद्रीय क्षेत्रक)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 63. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'मनरेगा (मनरेगा)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) वित्त मंत्रालय (B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (C) वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए (D) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'मनरेगा (मनरेगा)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **ग्रामीण विकास मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: वैधानिक अधिनियम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 64. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए (B) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) (C) वित्त मंत्रालय (D) जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय) **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **वित्त मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 24 2026 संकलन को स्वीकृत; 1 अप्रैल 2025 से लागू। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 65. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'एनपीएस वात्सल्य योजना'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) (B) जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय) (C) जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय) (D) वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'एनपीएस वात्सल्य योजना'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **वित्त मंत्रालय / पीएफआरडीए** है। विशेष तथ्य: 18 2026 संकलन। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 66. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम विश्वकर्मा योजना'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) (B) जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय) (C) जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय) (D) वित्त मंत्रालय **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम विश्वकर्मा योजना'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)** है। विशेष तथ्य: 17 सितंबर 2023; 13,000 करोड़ रु. (2023–28)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 67. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम-जनमन (पीएम-जनमन)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय) (B) जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय) (C) वित्त मंत्रालय (D) शिक्षा मंत्रालय **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम-जनमन (पीएम-जनमन)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 9 मंत्रालय)** है। विशेष तथ्य: 15 नवंबर 2023; 24,104 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 68. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) वित्त मंत्रालय (B) शिक्षा मंत्रालय (C) जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय) (D) शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट) **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान (डीएजेजीयूए)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **जनजातीय कार्य मंत्रालय (+ 17 मंत्रालय)** है। विशेष तथ्य: 2 2026 संकलन; 79,156 करोड़ रु.। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 69. 'योजना का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम मुद्रा योजना ('तरुण प्लस' विस्तार)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) शिक्षा मंत्रालय (B) शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट) (C) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) (D) वित्त मंत्रालय **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम मुद्रा योजना ('तरुण प्लस' विस्तार)'** (योजना का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **वित्त मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 8 अप्रैल 2015 (2026 संकलन में विस्तारित)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 70. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय / विभाग' के संदर्भ में, **'पीएम विद्यालक्ष्मी योजना'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) शिक्षा मंत्रालय (B) शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट) (C) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) (D) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम विद्यालक्ष्मी योजना'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय / विभाग' **शिक्षा मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 3,600 करोड़ रु. (2024–25 से 2030–31)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 71. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय / विभाग' के संदर्भ में, **'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) (B) शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट) (C) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (D) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय / विभाग' **शिक्षा मंत्रालय (इनफ्लिबनेट)** है। विशेष तथ्य: 6,000 करोड़ रु. (2025–2027)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 72. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय / विभाग' के संदर्भ में, **'पीएम इंटर्नशिप योजना'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (B) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) (C) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) (D) इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम) **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम इंटर्नशिप योजना'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय / विभाग' **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)** है। विशेष तथ्य: 2 लाख करोड़ रु. के पैकेज का भाग (5 वर्ष)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 73. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय / विभाग' के संदर्भ में, **'1,000 आईटीआई उन्नयन योजना'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) (B) इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम) (C) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (D) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'1,000 आईटीआई उन्नयन योजना'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय / विभाग' **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 60,000 करोड़ रु. (5 वर्ष)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 74. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय / विभाग' के संदर्भ में, **'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) (B) इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम) (C) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (D) कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय / विभाग' **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)** है। विशेष तथ्य: 50,000 करोड़ रु. (2023–28) + 1 लाख करोड़ अनुसंधान एवं विकास पूल। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 75. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय / विभाग' के संदर्भ में, **'इंडिया-एआई मिशन एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (B) इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम) (C) कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'इंडिया-एआई मिशन एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय / विभाग' **इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (इंडिया-एआई) एवं डीएसटी (क्वांटम)** है। विशेष तथ्य: 10,371.92 करोड़ रु. (इंडिया-एआई) एवं 6,003.65 करोड़ रु. (राष्ट्रीय क्वांटम मिशन)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 76. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'डिजिटल कृषि मिशन'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) (B) उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (C) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'डिजिटल कृषि मिशन'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 2,817 करोड़ रु. (2026 संकलन में स्वीकृत)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 77. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) (B) उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (C) वित्त मंत्रालय (D) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन)'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 2,481 करोड़ रु. (2026 संकलन में स्वीकृत)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 78. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (B) कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) (C) उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (D) वित्त मंत्रालय **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन)'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 10,103 करोड़ रु. (2024–25 से 2030–31)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 79. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (B) कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) (C) उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (D) वित्त मंत्रालय **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'क्लीन प्लांट प्रोग्राम (स्वच्छ पौध कार्यक्रम)'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **कृषि मंत्रालय (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)** है। विशेष तथ्य: 1,765.67 करोड़ रु. (एडीबी के सहयोग से)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 80. 'योजना / मिशन का नाम' एवं 'नोडल मंत्रालय' के संदर्भ में, **'पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (B) वित्त मंत्रालय (C) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (D) वित्त मंत्रालय (पीएफआरडीए) **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)'** (योजना / मिशन का नाम) का सही 'नोडल मंत्रालय' **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** है। विशेष तथ्य: 24 फरवरी 2019 (100% केंद्रीय क्षेत्रक)। (पत्र सूचना कार्यालय (PIB) एवं IUC Academy)